रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, 11 जून, 1983/ज्येष्ठ 21, 1905

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11, 1983/JYAISTHA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of Indi (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचनाएं

नई दिल्ली, 25 मई, 1983

का० आ० 2478.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री र० कृ० मालजी, वकील ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे भड़ौच, गुजरात में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं० 5(36)/83-जे]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTICES

New Delhi, the 25th May, 1983

S.O. 2478.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Sh. R. K. Malji, Advocate for appointment as a Notary to practise in Broach, Guiarat.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(36)/83-Judl.]

नई दिल्ली, 20 मई, 1983

का० आ० 2479.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक

आवेदन इस बात के लिए किया जा रहा है कि उसे जालंधर (पंजाब) व्यवहार करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं० 5 (42)/83-न्या०]

के० सी० डी० गंगवानी, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 20th May, 1983

S.O. 2479.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Vinod Kumar Sharma, Advocate Jalandhar City (Punjab) for appointment as a Notary to practise in Jalandhar.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice

[No. F. 5(42)/83-Judl.]

K. C. D. GANGWANI, Competent Authority

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 मई, 1983

का० आ० 2480.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10 ङ. की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्पनी कार्य विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सां० का० नि० संख्या 242 (ङ.) दिनांक 15 मार्च, 1976 का अधिलंघन करते पर, केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा 27 अप्रैल 1983 से यथा निम्नांकित रूप से कम्पनी विधि बोर्ड का पुनर्गठन करती है :—

(क) निम्नलिखित व्यक्ति कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्य होंगे, नामशः

1. श्री के० एस० भटनागर
2. श्री एस० एम० डुगर
3. श्री एस० चक्रवर्ती
4. श्री पी० के० मलिक
5. श्री के० डी० सक्सेना
6. श्री एस० सी० बाफना
7. श्री ए० आर० खरे

(ख) श्री के० एस० भटनागर, कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ।

[सं० ए-45011/45/83-प्रशा०]

आर० डी० मखीजा, अवर सचिव

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 23rd May 1983

S.O. 2480.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 10-E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of Department of Company Affairs Notification G.S.R. No. 242(E) dated the 15th March, 1976, as amended from time to time, the Central Government hereby reconstitutes the Company Law Board as indicated hereunder with effect from 27th April, 1983.

(a) The following persons shall be the Members of the Company Law Board, namely :—

1. Shri K. S. Bhatnagar
2. Shri S. M. Dugar
3. Shri S. Chakravarthi
4. Shri P. K. Mallik
5. Shri K. D. Saksena
6. Shri S. C. Bafna
7. Shri A. R. Khare.

(b) Shri K. S. Bhatnagar shall be the Chairman of the Company Law Board.

[No. A-45011/45/83-Admn. I]

R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 24 मई, 1983

का० आ० 2481.—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पी० आर० नामजोशी, अधिवक्ता, मुम्बई को, मुम्बई उच्च न्यायालय में मैसर्स अशोक इंडस्ट्रीज हैदराबाद के विरुद्ध आर० सी० 13/ई/70 मद्रास से उत्पन्न होने वाली दांडिक पुनरीक्षण अर्जी सं० 110/80 का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[संख्या 225/1/83-ए० वी० डी०-II]

हरिकृष्ण वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 24th May, 1983

S.O. 2481.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Central Government hereby appoints Shri P. R. Namjoshi, Advocate, Bombay, as Special Public prosecutor for conducting the Criminal Revision Petition No. 110/81 arising out of RC. 13/E/80 Madras against M/s. Ashoka Industries, Hyderabad, in the High Court of Bombay.

[No. 225/1/83-AVD. II]

H. K. VERMA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1983

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का० आ० 2482.—प्रत्यक्ष-कर बोर्ड (कार्य संचालन विनियमन) नियम 1964 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय

प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य तथा भारत सरकार के पदेन अपर सचिव श्री वी० चिदम्बरम् को, 24 मार्च, 1983 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[फा० सं० ए/19011/55/81-प्रशा० 1]
जी० एस० मेहरा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th March, 1983

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 2482.—In exercise of the powers conferred by Rule 3 of the Central Board of Direct Taxes (Regulation of Transaction of Business) Rules, 1964, the Central Government hereby appoints Shri V. Chidambaram Member, Central Board of Direct Taxes and ex-officio Additional Secretary to the Government of India, as Chairman of the Central Board of Direct Taxes with effect from the fore-noon of the 24th March, 1983 and until further orders.

[F. No. A-19011/55/81-Ad. II]
G. S. MEHRA, Under Secy

नई दिल्ली, 18 मई, 1983

आयकर

का० आ० 2483.—इस कार्यालय की दिनांक 25 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना सं० 3938 (फा० सं० 203/85/81-आ० क० नि० II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदन किया है, अर्थात :—

(i) यह कि अपर्णा आश्रम, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा-जोखा रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उन्हें सूचित किया जाए ।

(iii) यह कि उक्त संस्थान कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

सम्था

अपर्णा आश्रम, नई दिल्ली

यह अधिसूचना 25-4-83 से 24-4-1984 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 5186 (फा० सं० 203/1/83-आ० क० नि० II)]

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th May, 1983

INCOME TAX

S.O. 2483.—In continuation of the Office Notification No. 3938 (F. No. 203/85/81-ITA.II) dated 25th April, 1981, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Aparna Ashram, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research,

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expediture and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income tax

INSTITUTION

Aparna Ashram, New Delhi

This notification is effective for a period of one year from 25-4-1983 to 24-4-1984.

[No 5186(F. No. 203/1/83-ITA.II)]

आयकर

का० आ० 2484.— सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 (ii) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2 क) के प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित कर दिया गया है —

1. वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना :	स्टडीज आन ट्रेन-स्किपणून रम्लीकेशन एण्ड परसिसटेन्ट इन्फैक्शन आफ हिन्डरपेस्ट वायरस ।
2. समर्थक का नाम.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई ।

3. कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला :	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस बंगलौर ।
4. प्रारम्भ करने की तारीख	15-4-1983
5. पूरा करने की तारीख	14-4-1986
6. परियोजना की अवधि	3 वर्ष
7. अनुमानित लागत	रु० 3,68,420-

2 इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (2) (xiii) के अन्तर्गत अनुमोदित है । वैज्ञिय वित्त संत्रालय की दिनाक 23-11-1946 की अधिसूचना संख्या 34

[सं० 5188 (फा० सं० 203/30/82-आ० क० नि II)]

S O. 2484—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 (iv) of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi :

1. Scientific Research Project	: Studies on transcription, replication and persistent infection of hinderpest virus.
2. Name of the Sponsorer	: Hindustan Lever Limited, Bombay,
3. Implementing Lab	: Indian Institute of Science, Bangalore.
4. Date of commencement	: 15-4-1983
5. Date of completion	: 14-4-1986
6. Duration of the project	: 3 years
7. Estimated cost	: Rs. 3,68,420/-

2. Indian nstitute of Science, Bangalore stands approved under section 10 (2) (xiii) of the Income-tax Act, 1922 vide Ministry of Finance Notification No. 34 dated 23-11-1946.

[No. 5188 (F. No. 203/30/82-I TA.II)]

नई दिल्ली, 19 मई, 1983

आय-कर

का० आ० 2485.— सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात :—

(i) यह कि कालेज आफ टैक्नोलाजी, सीरामपुरी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा-जोखा रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त कालेज, अपने वैज्ञानिक अनुसधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उन्हें सूचित किया जाए ।

(iii) यह कि उक्त कालेज अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तिया देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रति वर्ष विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सबंधित आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

कालेज आफ टैक्नालाजी, सीरामपुर

यह अधिसूचना 13-2-1983 से 12-2-1986 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 5193(फा०स०203/207/82-आ०क०नि II)]

New Delhi, the 19th May, 1983

INCOME TAX

S.O. 2485.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions : —

(i) That the College of Textile Technology, Serampore will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research,

(ii) That the said College will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said College will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

College of Textile Technology, Serampore.

This notification is effective for a period of three years from 13-2-1983 to 12-2-1986.

[No. 5193(F No. 203/207/82-IT.A II)]

आय-कर

का० आ० 2486.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य क्रम को नीचे दी गई विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उप-धारा (2 क) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है :—

1.	अनुसंधान परियोजनाओं का नाम	: (1) स्ट्रक्चरल रिटर्न लास मेजरमेंट इन हाई फ्रिक्वेंसी कोएक्सीयल केबल्स । (2) इलैक्ट्रोकेमिकल कंट्रोल आफ एनवायरनमेंटल पोल्यूशन ।
2	प्रायोजक का नाम	मेसर्स गर्ग एसोसिएट्स प्रा० लि०, गाजियाबाद ।
3	कार्यान्वयन प्रयोगशाला	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।
4	प्रारम्भ करने की तारीख	अप्रैल 1982
5	समापन की तारीख	मार्च, 1983
6.	अनुमानित व्यय	2,00,000 रुपए

2. भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर, को वित्त मंत्रालय के दिनांक 23-11-1946 की अधिसूचना सं० 34 द्वारा आय-कर अधिनियम 1922 की धारा 10 (2) (xiii) के अंतर्गत अनुमोदित कर दिया गया है ।

[सं० 5194 (फा० सं० 230/7/83-आ० क० नि०-II)]
एम० जी० सी० गोयल, अवर सचिव

INCOME-TAX

S.O. 2486.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule of 6 the Income-tax Rules 1962 by Department of Science & Technology, New Delhi:

1.	Title of Research Projects :	(i) Structural Return loss Measurement in High Frequency Coaxial Cables. (ii) Electrochemical Control of Environmental Pollution.
2.	Name of Sponsorer	: M/s. Garg Associates Pvt. Ltd., Ghaziabad.
3.	Implementing Lab	: Indian Institute of Science, Bangalore.
4.	Date of commencement	: April, 1982
5.	Date of completion	: March, 1983
6.	Estimated cost	: Rs. 2,00,000/-

2. Indian Institute of Science, Bangalore stands approved u/s 10 (2) (xiii) of the I.T. Act, 1922 vide Ministry of Finance Notification No. 34 dated 23-11-1946.

[No. 5194 (F. No. 203/7/83-IT A.II)]
M.G.C. GOEL, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून, 1983

का०आ० 2487.—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण ("अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष" के लिए निर्मित एक सौ रुपए के चांदी प्रूफ और एक सौ रुपए के चांदी पाइफोर्ट स्मारक सिक्कों का जिनमें से प्रत्येक में 0.925 परिष्कृत स्टर्लिंग चांदी होगी, मानक वजन और उपचार) नियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के लिए निर्मित कतिपय मूल्य-वर्ग के सिक्कों का मानक वजन और अनुज्ञात उपचार ।

अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के संस्मरण में सिक्का-निर्माण अधिनियम 1906 (1906 का 3) की धारा 6 के उपबंधों के अधीन निर्मित निम्नलिखित मूल्य-वर्ग के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों के निर्माण में अनुज्ञात उपचार वैसा होगा जैसा नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है—

सारणी

सिक्के का मूल्य-वर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संरचना में	वजन में
एक सौ रुपए के चांदी प्रूफ	29.16 ग्राम	चांदी के लिए 0.1% धन या ऋण	1/100 वां धन या ऋण
एक सौ रुपए के चांदी पाइ-फोर्ट	38.32 ग्राम	चांदी के लिए 0.4—धन या ऋण	1/100 वां धन या ऋण

[सं० एफ 1/19/(1)/80-बजायन]

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 1st June, 1983

S.O. 2487.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906); the Central Government hereby makes the following rules. :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of the Commemorative Coins of One Hundred Rupees Silver Proof and One Hundred Rupees Silver Piefort each containing 0.925 fine Sterling Silver coined for "International Year of the Child") Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Standard weight and remedy allowed on coins of certain denominations coined for International Year of the Child.

The standard weight of the coins of the following denominations coined under the Provisions of section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906) in commemoration of International Year of the Child, and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table below :—

TABLE

Denomination of the Coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In weight
One hundred Rupees Silver Proof	29.16 grammes	0.4% plus or minus for silver.	1/100th plus or minus.
One hundred Rupees Silver Piefort	58.32 grammes	0.4% plus or minus for silver	1/100th plus or minus.

[No. F.1/19(I)/80-Coin]

का०आ० 2488.—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अवधारित करती है कि—

(क) निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्के भी अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के संस्मरण में केन्द्रीय सरकार के प्राधिकाराधीन जारी किए जाने के लिए टकसाल में बनाए जाएंगे अर्थात् –

(i) एक सौ रुपए के चांदी प्रूफ

(ii) एक सौ रुपए के चांदी पाइफोर्ट

(ख) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विभाओं, डिजाइनों और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:—

सिक्के का अंकित मूल्य	आकार और बाहरी व्यास	सिरेशनों की संख्या	धातु संरचना
एक सौ रुपए के चांदी प्रूफ	वृत्ताकार 44 मिमी	200	0.925 शुद्ध स्टर्लिंग-चांदी
एक सौ रुपए के चांदी पाइफोर्ट	वृत्ताकार 44 मिमी	200	0.925 शुद्ध स्टर्लिंग चांदी

डिजाइन.

एक सौ रुपए के चांदी प्रूफ और एक सौ रुपए के चांदी पाइफोर्ट:

मुख भाग : सिक्कों के मुख भाग पर अशोक स्तंभ के सिंह गुम्बज के साथ "सत्यमेव जयते" सार वाक्य नीचे अंकित होगा और उसके बायें ऊपरी भाग में "भारत" शब्द और दायें ऊपरी भाग में "India" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "100" अंतरराष्ट्रीय अंकों में लिखा होगा और उसके बायें निचले भाग में "रुपए" शब्द और दायें निचले भाग में "Rupees" शब्द अंकित होगा।

पृष्ठ भाग : सिक्के के इस भाग पर "International year of the child" लिखा होगा। मध्य में एक भारतीय नृत्यांगना और चार संगीतकार चित्रित किए जाएंगे। चार संगीतकारों में से एक लड़का होगा, जो नृत्यांगना के बायें "सितार" बजा रहा होगा, सबसे ऊपर एक लड़का और लड़की "वीणा" बजा रहे होंगे और दायें एक लड़का "मृदंग" बजा रहा होगा। परिधि के चारों ओर ऊपरी अर्ध भाग में "अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष" और निचले अर्ध भाग में "INTERNATONAL YEAR OF THE CHILD तथा वर्ष, 1981 अंकित होगा। दायें भाग में भी "INTERNATIONAL YEAR OF THE CHILD" का प्रतीक और बायें भाग में "United Nations Children's Fund" का प्रतीक अंकित होगा।

[सं० एफ०/1/19(II)/80-अवायन]

सी० जी० पाथरोस, अवर सचिव

S.O. 2488.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that—

(a) the coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government in commemoration of the International Year of the Child, namely :—

(i) One hundred Rupees, Silver Proof,

(ii) One hundred Rupees Silver Piefort

(b) the coins of the above denomination shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely :—

Denomination of the coin	Shape and out side diameter	Number of serrations	Metal composition
One Hundred Rupees Silver Proof	Circular 44 millimetre	200	0.925 fine sterling Silver
One Hundred Rupees Silver Piefort	Circular 44 millimetre	200	0.925 fine sterling Silver

DESIGN :

One hundred rupees Silver Proof and One hundred rupees Silver Piefort :

OBVERSE : This face of the coins shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar, with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "100" in international numerals flanked on the left lower periphery with the words "रुपये" and on the right lower periphery with the word "Rupees".

REVERSE : This face of the coins shall have the theme "International Year of the Child". In the centre, an Indian dancing girl and four musicians shall be depicted. The four musicians shall be a boy playing *Sitar* on the left side of the dancing girl a boy and a girl playing *Veena* at the top and a boy playing *Mrudanga* on the right. Around the periphery, the upper half shall bear the inscription "अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष" and the lower half the inscription "INTERNATIONAL YEAR OF THE CHILD" and the year "1981". The right periphery also bears the symbol of "International Year of the Child" and the left periphery the symbol of the "United Nations Children's Fund".

[No. F 1/19/(11)/80-Coin]
C. G. PATHROSE, Under Secy.

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, 16 मई, 1983

का० आ० 2489.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एम० आर० बी० पुंजा को, जो कि 16 मई, 1983 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, इसी तारीख से औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[संख्या 9/7/83-बी० ओ० (2)]
(Banking Division)

New Delhi, the 16th May, 1983

S.O. 2489.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri M. R. B. Punja, who has been appointed as the Managing Director of the Industrial Development Bank of India with effect from the 16th May, 1983, to be the Chairman of the Board of Directors of the Industrial Development Bank of India with effect from the same date.

[No. F. 9/7/83-BO. I (2)]

नई दिल्ली, 16 मई, 1983

का० आ० 2490.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम० आर० बी० पुंजा को 16 मई, 1983 से आरम्भ होने वाली तथा 14 दिसम्बर, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/7/83-बी० ओ० 1 (1)]
चा० वा० मीरचन्दानी, उप सचिव

S.O. 2490.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) and of sub-section (2) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri M. R. B. Punja as the Managing Director of the Industrial Development Bank of India for the period commencing on the 16th May, 1983 and ending with the 14th December, 1985.

[No. F. 9/7/83-BO. I (1)]
C. W. MIRCHANDANI, Dy Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 1983

का० आ० 2491.—यतः बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार ने नेशनल बैंक आफ लाहौर लि० दिल्ली के भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय के लिए 20 फरवरी 1970 को एक योजना मंजूर की थी ।

यतः उक्त योजना के खण्ड 6 के उपखण्ड (9) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नेशनल बैंक आफ लाहौर, लि० दिल्ली की परिसम्पत्तियों का अंतिम रूप से मूल्यांकन नियत तारीख से बारह वर्षों की समाप्ति के पश्चात् अपेक्षित था जो कि नियत तारीख को अनन्तिम रूप से मूल्यांकित कर लिया गया है ।

यतः भारतीय स्टेट बैंक ने यह अभ्यावेदन किया है कि बड़ी संख्या में परिसम्पत्तियां अंतर्ग्रस्त होने और बैंक के प्रयासों के बावजूद अधिकांश पदों की वसूलियां अभी बाकी होने के कारण बैंक, विलय योजना के खण्ड 6 के उपखण्ड (9) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर परिसम्पत्तियों का अंतिम रूप से मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा है।

और यतः केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद इस बात से संतुष्ट है कि विलय योजना को लागू करने में कठिनाई पैदा हो गयी है और उतना समय बढ़ा कर जितने में परिसम्पत्तियों का अंतिम रूप से मूल्यांकन अपेक्षित है उक्त कठिनाई को दूर करना जरूरी है।

अतः अब नेशनल बैंक आफ लाहौर लि० दिल्ली के भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय की 20 फरवरी 1970 की विलय योजना के खण्ड 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा उसके अनुमोदन से नेशनल बैंक आफ लाहौर लि०, दिल्ली की उन परिसम्पत्तियों का जिनकी वसूली और मूल्यांकन नहीं हुआ है नियत तारीख से पन्द्रह वर्षों की अवधि के भीतर मूल्यांकन करेगा।

New Delhi, the 23rd May, 1983

S.O. 2491.—Whereas on 20th February, 1970 a scheme of amalgamation of the National Bank of Lahore Ltd, Delhi with the State Bank of India was sanctioned by the Central Government in exercise of the powers conferred by and in accordance with Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949.

Whereas under sub-clause (ix) of clause 6 of the said scheme, the State Bank of India was required to make a final valuation of the assets of the National Bank of Lahore Ltd., Delhi which have been provisionally valued on the prescribed date on the expiry of twelve years from the prescribed date.

Whereas the State Bank of India has represented that in view of the large number of assets involved and the recovery of most of the items yet to be realised in spite of its efforts it has not been able to make the final valuation within the time specified in sub-clause (ix) of clause 6 of the scheme of amalgamation

And whereas the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India is satisfied that a difficulty has arisen in giving effect to the scheme of amalgamtion which it is necessary to remove by extending the time within which the final valuation of assets is required to be made

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause 21 of the scheme of amalgamation dated 20th February 1970 of the National Bank of Lahore Ltd, Delhi with the State Bank of India, the Central Government hereby directs that the State Bank of India shall in consultation with and with the approval of the Reserve Bank of India value the assets of the National Bank of Lahore Ltd Delhi which have not been realised and valued, within a period of fifteen years from the prescribed date

[No 17/6/82-B.O. III]

का० आ० 2492.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के फार्म "क" के साथ संलग्न टिप्पणी (च) के उपबंध 31 दिसम्बर 1982 की स्थिति के अनुसार तैयार किए गए निम्नलिखित बैंकों के तुलन-पत्रों पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जब उक्त फार्म की सम्पत्ति तथा परिसम्पत्ति शीर्ष की मद 4 के उपशीर्ष (2), (3), (4) और (5) के सामने अन्दर के कालम के दिखाया गया मूल्य उस उपशीर्ष के अन्तर्गत निवेशों के बाजार मूल्य से बढ़ जाएगा। उस उपशीर्ष के अंतर्गत किए गए निवेशों का बाजार मूल्य कोष्ठकों के अन्दर अलग से दिखाया गया है —

1 दि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०

2 यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

[संख्या 15/2/83-बी० ओ० III]

एन० डी० बत्रा, अवर सचिव

S.O. 2492.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the form 'A' in the Third Scheduled to the said Act shall not apply to the following banks, viz :—

1. The Lakshmi Commercial Bank Ltd,

2 United Commercial Bank,

In respect of their balance-sheet as on the 31st December, 1982 which when the value shown in the inner column against any of the sub-heads (ii) (iii), (iv) and (v) of the item 4 of the Property and Assets side of the said Form exceeds the market value of the investments under that sub-head, shows separately within brackets the market value of the investments under that sub-head

[No. 15/2/83-B.O. III]
N D BATRA, Under Secy

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क समाहर्ता का कार्यालय

सीमा शुल्क

बंगलौर, 6 मई, 1983

का० आ० 2493.—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं सी. के गोपालकृष्णन, समाहर्ता सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर्नाटक समाहर्तालय, बंगलौर एतद्द्वारा दिनांक 29-12-81

की अधिसूचना सं० 3/81 की वैधता को दिनांक 31-3-86 तक विस्तरित करता हूं और मैसर्स कर्नाटक इंजीनियरिंग और मेरिन कम्पनी, बंगलौर को बेजेज तथा नौकर उपस्कर स्टोर करने तथा स्टील बरेज और नौकाओं को तैयार करने तथा नौभरण हेतु, इस समाहर्तालय द्वारा जारी दिनांक 23 सितम्बर, 1968 में पिछली अधिसूचना के अनुलग्न सारणी में विनिर्दिष्टत, पोर्ट-लैंड जिसका माप 2671.30 वर्ग मीटर (टी. एस. नं. 1587/1 ब्लाक 31) पोर्ट आफ् रॉफ नं. 48, मंगलौर को इस्तेमाल करने की अनुमति देता हूं।

[अधिसूचना सं० 1/83 सीमाशुल्क/ सी. नं. VIII/48/226/79 सी. 2 सीमा०]
सी०के० गोपालकृष्णन्, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, बंगलोर

(Department of Revenue)

(Office of the Collector of Central Excise and Customs)

Bangalore, the 6th May, 1983

CUSTOMS

S.O. 2493.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Customs Act, 1962, I C. K. Gopalakrishnan, Collector of Customs and Central Excise, Karnataka Collectorate, Bangalore, hereby extend the validity of the notification No. 3/81 dated 29th December, 1981 upto 31-3-86 and permit M/s. Karnataka Engineering and Marine Company, Mangalore to use the port land area measuring 267.30 Square metres (T.S. No. 1587/1 Block 31) Part of Wharf No. 48 Mangalore specified in the table appended to the earlier Notification dater 23rd September, 1983 issued by this Collectorate for the purpose of storing barges and boat equipments. to manufacture steel barges and boats and for shipments thereof.

[Notification No. 1/83.Cus.C.No.VIII/48/226.79 C2Cus.]
C. K. GOPALAKRISHNAN, Collector of Customs & Central Excise Bangalore

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 1983

का. आ. 2494.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना-का. आ. 74 तारीख 1 जनवरी, 1983 के संशोधन में अपर सचिव-वाणिज्य मंत्रालय का निर्यात निरीक्षण परिषद् के सदस्य के रूप में पदनामित करती है।

[फाईल सं. 3(94)/75-ई. आई. एण्ड ई. पी.]
सी. बी. कुकरेती, संयुक्त निदेशक,

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 21st May, 1983

S.O. 2494.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with Rules 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government in modification of Notification S.O. 74 dated 1st January, 1983 hereby designates Additional Secretary, Ministry of Commerce as Member of the Export Inspection Council.

[F. No. 3(94)/75-EI&EP]
C. B. KUKRETI, Jt. Director

मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली 28 मई, 1983

का०आ० 2495:—सर्वश्री इण्डियन गैसिज (प्रोप्राइटर कान्हजी गैसिज प्रा० लि०) ग्वालियर को मुक्त विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत 40 लीटर क्षमता के 872 खाली आक्सीजन गैस सिलेंडरों के आयात के लिए 4,37,024-रु० (चार लाख सैंतीस हजार चौबीस रुपए मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं० पी०/सी०जी०/2082077/सी० एक्स एक्स०/77/एच०/79/सी०जी०—3 दिनांक 31-12-1980 प्रदान किया गया था। बाद में आयात लाइसेंस का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य बढ़ाकर 4,50,631-रु० ($57,552) कर दिया गया था। फर्म द्वारा पहले किए गए आवेदन पर उपर्युक्त आयात लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द कर दी गई थी, देखिए भारत के (साधारण) राजपत्र के भाग—2 खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित आदेश सं० सी०जी० 3/437/78/19/ दिनांक 8-6-1982 और उसके पश्चात् उन्हें अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति सं० डी०-2468098 दिनांक 10-6-82 जारी की गई थी।

अब फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि प्रतियों जारी करने के लिए इन आधारों पर आवेदन किया है कि लाइसेंस सं० पी/सी जी/2082077 दिनांक 31-12-1980 की सीमा-शुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां और लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति के बदले में जारी की गई अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति सं० डी—2468098 दिनांक 10-6-1982 खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई थी। आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस (लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति सहित) किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

अपने तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने ग्वालियर के नोटरी पब्लिक के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार में संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं० पी/सी जी/2082077 दिनांक 31-12-1980 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति और सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति (अनुलिपि सं० डी—2468098 दिनांक 10-6-1982) फर्म से खो गई या अस्थानस्थ हो गई है। यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 के उप-खंड 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री इंडियन गैसिज (प्रोप्राइटर कान्हजी गैसिज प्रा०लि०), ग्वालियर को जारी

किए गए आयात लाइसेंस सं० पी/सी जी/2082077 दिनांक 31-12-1980 की उक्त मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति और सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति (अनुलिपि सं० डी-2468098 दिनांक 10-6-1982) एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क और मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सीoजीo-3/437/78/19]

शंकर चन्द, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports,
New Delhi

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1983

S.O. 2495.—M/s. Indian Gases (Prop. Kanhji Gases Pvt. Ltd., Gwalior were granted an import licence No. P/CG/2082077/C/XX/77/H/79/CGIII dated 31-12-1980 for Rs. 4,37,024 (Rupees four lakhs, thirtyseven thousand and twenty-four only) for import of 872 Nos. of empty oxygen gas cylinders of 40 litres capacity under Free Foreign Exchange. The CIF value of the import licence was subsequently enhanced to Rs. 4,50,681 ($ 57,552). On firm's request made by them earlier the Customs Purposes Copy of the above import licence was cancelled vide Order No. CG III/437/78/19 dated 8-6-1982 published in the Gazette of India (Ordinary) Part II Section 3 Sub-section (ii) and thereafter Duplicate Customs Purposes Copy No. D-2468098 dated 10-6-82 was issued to them.

The firm has now applied for issue of Duplicate copies of Customs and Exchange Control Purposes of the above mentioned licence on the grounds that the Customs and Exchange Control Purposes Copies of the licence No. P/CG/2082077 dated 31-12-80 and also the Duplicate Customs Purposes Copy bearing No. D-2468098 dt. 10-6-82 issued in lieu of the Customs Purposes Copy of the licence had been lost or misplaced. It has further been stated that the licence (including Duplicate Customs Purposes Copy of the licence) was not registered with any Customs authority and as such the value of Customs Purposes Copy has not been utilised at all.

In support of their contention, the licensee has filed an Affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public, Gwalior. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes Copy and Custom Purposes Copy (Duplicate No. D-2468098 dt. 10-6-82) of import licence No. P/CG/2082077 dated 31-12-80 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said Exchange Control Purposes Copy and Customs Purposes Copy (Duplicate No. D-2468098 dated 10-6-82) of the import licence No. P/CG/2082077 dated 31-12-80 issued to M/s. Indian Gases (Prop. Kanhji Gases Pvt. Ltd.), Gwalior are hereby cancelled.

A duplicate Customs and Exchange Control Purposes Copies of the said licence are being issued to the party separately.

[No. CG.III/437/78/19]

SHANKAR CHAND, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

नई दिल्ली, 7 मई, 1983

का० आ० 2496—यतः दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खंड (घ) के अनुसरण में मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर की सीनेट ने डा० रामदास एम० ई० चिकित्सा निदेशक, कस्तूरबा मेडिकल कालेज और अस्पताल मणिपाल को 21 मार्च, 1983 से दंत चिकित्सा परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 12 अप्रैल, 1949 की अधिसूचना सं० 10-10/48 एम० I में जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 9 फरवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 533 में पुनः प्रकाशित हुई है निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्—

उक्त अधिनियम में "धारा 3 के खंड (घ) के अधीन (घ) निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 15 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात—

"16. डा० राम दास एम० पई, चिकित्सा निदेशक, कस्तूरबा मेडिकल कालेज और अस्पताल मणिपाल (कर्नाटक)	मंगलौर विश्वविद्यालय	21-3-1983"

[सं० वी० 12013/3/83—पी०एम०एस०]

एस० पी० पाठक, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 20th May, 1983

S.O. 2496.—Whereas in pursuance of clause (d) of section (3) of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Dr. Ramdas M. Pai, Medical Director, Kasturba Medical College and Hospital, Manipal, has been elected to be a member of the Dental Council of India by the Senate of the Mangalore University, Mangalore, with effect from the 21st March, 1983,

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health No. 10-10/48-MI, dated the 12th April 1949, as republished by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 533, dated the 9th February, 1978, namely:—

In the said notification, under the heading "(d) Elected under clause (d) of section 3", after serial number 15 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

"16. Dr. Ramdas M. Pai, Medical Director, The Kasturba Medical College and Hospital, Manipal (Karnataka)	University of Mangalore	21.3.83."

[No. V-12013/3/83-PMS]

S. P. PATHAK, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 1983

का० आ० 2497—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धों का पालन करते हुए बरहामपुर विश्वविद्यालय की सीनेट ने रिक्त पद पर एम० के० सी० जी० मेडिकल कालेज, बरहामपुर के प्रिंसिपल डा० पी० के० कार को 23 मार्च, 1982 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या एम० ओ० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 39 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

"39, डा० पी० के० कार,
प्रिंसिपल, एम० के० सी० जी० मेडिकल कालेज,
बरहामपुर ।"

[सं० वी० 11013/11/83-एम० ई० (पी)]
पी० सी० जैन, अवर सचिव

New Delhi the 24th May, 1983

S.O. 2497.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of Sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. P. K. Kar, Principal, M. K. C. G. Medical College, Berhampur has been elected in the vacant post by the Senate of Bernampur University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 23rd March 1982;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health No. S. O. 138 dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of Sub-Section (1) of Section 3", for Serial Number 39 and the entries relating thereto the following Serial Number and entries shall be substituted namely :—

"39, Dr. P. K. Kar.,
Principal, M. K. C. G Medical College,
Berhampur."

[No. V 11013/11/83-ME (P)]
P. C JAIN, Under Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 1983

का० आ० 2498.—केन्द्रीय सरकार कयर उद्योग अधिनियम 1953 (1953 का 45) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कयर उद्योग नियम, 1954 का कतिपय और संशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति के प्राप्त होने केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कयर उद्योग (संशोधन) नियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. कयर उद्योग नियम 1954 में,—

(क) नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"18. बोर्ड का लेखा :—(1) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में संबंधित आय और व्यय, साथ ही आस्तियों और दायित्वों का, अनुसूची में उपवर्णित प्ररूपों में लेखा रखेगा ।

(2) आय और व्यय तथा आस्तियों और दायित्वों का संपरीक्षित लेखा और उसके साथ उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट, किसी मामले में ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा के पश्चात् ऐसे वर्ष की जिससे लेखा संबंधित है समाप्ति से सात मास तक न कि उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) आय के लेखा निम्नलिखित शीर्षों के नीचे दर्शित किए जाएंगे :—

(क) अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्राप्त धन

(ख) केन्द्रीय सरकार से, अधिनियम की धारा 14का के अधीन प्राप्त अनुदान ।

(ग) बोर्ड द्वारा प्राप्त कोई अन्य धन

(घ) विनिधानों पर ब्याज

(ङ) बिजली करघा कारखाने (हिन्दुस्तान कयर) के व्यय पर आय का अधिव्यय ।

(च) शो रूमों और विक्रय डिपों में व्यय पर आय का आधिक्य ।

(4) वर्ष में उपगत व्यय भिन्न-भिन्न शीर्षों और उपशीर्षों के अधीन दर्शाया जाएगा जैसा कि अनुसूची में दिया गया है ;

(ख) अनुसूची में प्ररूप 2 और 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे अर्थात् :—

"प्रारूप—2"

[नियम 18(1) देखिए]

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए कयर बोर्ड शो रूम और विक्रय डिपो का आय और व्यय लेखा

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	व्यय का शीर्ष	चालू वर्ष के आंकड़े		पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	आय		चालू वर्ष के आंकड़े
रु० पै०		अनुसूची	रु० पै०	रु० पै०		अनुसूची	रु० पै०
	वेतन	1			विक्रय पर कमीशन	2	
	शोरूम और विक्रय डिपो के प्रबंधकों को कमीशन	2			प्रकीर्ण प्राप्तियां	6	
	बीमा किराया						
	रेट और कर अवक्षयण	3			आय पर व्यय का आधित्य		
	आस्थगित राजस्व बट्टे खाते डाला गया व्यय अन्य प्रकार	4					
	व्यय कर आय का आधित्य	—	—	—		—	—
	योग	—	—	—		—	—

प्रारूप —3

[नियम 18 (1) देखिए]

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए विनिर्माण और व्यवसाय लेखा

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	व्यय	चालू वर्ष के आंकड़े		पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	आय	चालू वर्ष के आंकड़े
रु० पै०		रु० पै०		रु० पै०		रु० पै०
	प्रारंभिक स्टाक :				व्यापार लेखा में अन्तरित	
	कच्ची सामग्री रंजक और रसायन				परिरूपित माल की लागत	
	अर्ध परिरूपित माल चालू कार्य				अंतिम स्टाक]	
	अन्य क्रय रंजन प्रभार				कच्ची सामग्री रंजक और	
	स्नेहक जल और विद्युत मजदूरी				रसायन अर्ध परिरूपित माल	
	भविष्य निधि और कर्मचारी				चालू कार्य	
	अभिदाय कर्मकारों को बोनस				अन्य विक्रय	
	सामान लाने का प्रभार				परेषण लेखा पर विक्रय	
	अवक्षयण भवन सयंत्र और मशीनरी				परिरूपित माल का अंतिम स्टाक	
	औजार आदि विनिर्माण लेखा से				लाभहानि लेखा में अंतरित कुल हानि	
	अंतरित परिरूपित माल की लागत					
	परिरूपित माल का प्रारंभिक स्टाक	—	—			—
—	लाभ और हानि लेखाओं का कुल लाभ	—	—			—
—	योग					

प्रारूप 4

[नियम 18(1) देखिए]

31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	व्यय का शीर्ष	चालू वर्ष के आंकड़े	पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	लेखा का शीर्ष	चालू वर्ष के आंकड़े
रु० पै०	वेतन और भत्ते	रु० पै०	रु० पै०	व्यापार खाते	रु० पै०
	यात्रा भत्ता			अंतरित	
	भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य			कुल लाभ	
	बीमा में अभिदाय डाक महसूल और तार			प्रकीर्ण प्राप्तियां	
	दूरभाष स्टे				
	रेट और कर				
	ब्याज				
	बीमा				
	भवनों की मरम्मत और अनुरक्षण				
	मशीनरी की मरम्मत और अनुरक्षण				
	माल ले जाने का प्रभार				
	बैंक प्रभार				
	छूट				
	विज्ञापन प्रभार				
	प्रशिक्षुओं को वृत्तिका				
	लेखन सामग्री और मुद्रण				
	कार्यालय व्यय				
	अवक्षयण				
	फर्नीचर और फिटिंग्स आदि				
	विविध व्यय	—	—	कुल हानि	—
—	कुल लाभ				
—	योग	—	—		—

प्रारूप 5

[नियम 18 (1) देखिए]

31 मार्च को तुलन पत्र

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	दायित्व	चालू वर्ष के आंकड़े	पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	आस्तियां		चालू वर्ष के आंकड़े
रु० पै०	पूंजी	रु० पै०	रु० पै०	स्थिर आस्तिया	अनुसूची	रु० पै०
	अंतिम तुलन पत्र के अनुसार शेष			चालू आस्तिया	7	
	लाभ और हानि लेखा			अंतिम स्टाक		
	अंतिम तुलन पत्र से लिया गया कुल लाभ			कच्ची सामग्री		
	वर्ष के दौरान हुए लाभ को जोड़िए			रसायन		
	भारत सरकार से ऋण बैंक के ऋण					
				अर्धपरिरूपित माल		
	चालू दायित्व			चालू कार्य		
	विविध लेनदार			परिरूपित माल		
	बकाया ब्याज			शो रूमों में स्टाक		
	निक्षेप अग्रिम			विविध ऋणी		
—	अन्य दायित्व			शो रूम		
—	योग	—	—	अन्य	—	
—				हाथ में स्टाम्प	—	
				बैंक में रोकड़		
				ऋण और अग्रिम		
				वसूलनीय जेमा		
				कर्मचारियों को अग्रिम		
				अन्यों को अग्रिम		

प्रारूप 6

[नियम 18 (1) देखिए]

31 मार्च का समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कयर बोर्ड का आय और व्यय लेखा

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकडे	व्यय का शीर्ष		चालू वर्ष के आंकडे	पूर्ववर्ती वर्ष के आंकडे	आय का शीर्ष		चालू वर्ष के आंकडे
रु० पै०		अनुसूची	रु० पै०	रु० पै०		अनुसूची	रु० पै०
	प्रशासन	8			कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 14 के अधीन प्राप्त धन उपकर संग्रहण प्रभार कम कीजिए कयर उद्योग अधिनियम 1953 की धारा 14क के अधीन भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		
	स्थानीय मंडियों का विस्तार						
	विदेशी मंडियों का विस्तार						
	अनुसंधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी	9					
	सांख्यिकी प्रलेखीकरण और आंकड़ों आधार विपणन और प्रचार	10			अन्य प्राप्तियां	13	
	राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं को मजबूत बनाना				विनिधानों पर ब्याज आय		
	निर्यात विनियमन और निरीक्षण-निम्नतम विक्रय/मूल्य कयर सहकारिता) अखिल भारतीय) के लिए समर्थन	11			पर व्यय का आधिक्य		
	आधारिक संरचना प्रशिक्षण के लिए समर्थन				हिन्दुस्तान कयर व्यय का आय पर आधिक्य		
	सर्वेक्षण और अध्ययन						
	केन्द्रीय विपणन संगठन की स्थापना संघटक योजना						
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति	12					
	अन्य						
	सदस्यों को यात्रा भत्ता						
	अवक्षयण						
	ऋणों पर ब्याज						
	शोरूम के व्यय पर आय का आधिक्य						

प्रारूप 7

[नियम 18 (1) देखिए]

31 मार्च, को कयर बोर्ड का तुलन पत्र

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकडे	दायित्व		चालू वर्ष के आंकडे	पूर्ववर्ती वर्ष के आंकडे	आस्तियां		चालू वर्ष के आंकडे
रु० पै०	पूंजी	अनुसूची	रु० पै०	रु० पै०		अनुसूची	रु० पै०
1	2		3	4	5		6
	अंतिम तुलन पत्र के अनुसार बकाया				स्थिर आस्तियां	14	
	कयर निधि लेखा				विनिधान चालू		
	प्रारंभिक बकाया				आस्तियां	15	
	कम कीजिए वर्ष के दौरान				अंतिम स्टाक		
					शोरूम में स्टाक		

1	2	3	4	5	6
	व्यय पर आय का आधिक्य			विविध ऋणी	16
	भारत सरकार से ऋण			शोरूम	
	चालू दायित्व			हिन्दुस्तान कयर	
	विविध लेनदार			अन्य	
	बकाया ब्याज			हाथ में स्टाम्प	
	जमा अग्रिम			हाथ में रोकड	
	अन्य दायित्व			बैंक में चालू खाते में रोकड	
				बैंक में जमा खाते में रोकड	
				ऋण और अग्रिम	
				वसूलनीय जमा	
				कर्मचारियों को अग्रिम	
				अन्यों को अग्रिम	
				कयर निधि लेखा	
--	योग		--	-- प्रारम्भिक बकाया	--
—			—	— जोड़िए, आय पर व्यय का आधिक्य	—

[फा०सं० (3) 7-आई०सी०सी० (कयर)]

एम०के० चक्रवर्ती, उपसचिव

टिप्पण : कयर उद्योग नियम, 1954 भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग 2 भाग 3 पृष्ठ 1109 से 1116 पर अधिसूचना सं० सां०का०नि०आ० 2226 तारीख 6-7-1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। निम्नलिखित द्वारा उनका संशोधन किया गया.

(1) अधिसूचना सं० का०नि०आ० 973 तारीख 29-4-1955
(2) अधिसूचना सं० का०नि०आ० 3669 तारीख 17-12-1955
(3) अधिसूचना सं० का०नि०आ० 3983 तारीख 12-12-1955
(4) अधिसूचना सं० का०आ० 877 तारीख 9-4-1960
(5) अधिसूचना सं० सां०का०नि० 1088 तारीख 18-6-1963
(6) अधिसूचना सं० का०आ० 1744 तारीख 6-5-1967
(7) अधिसूचना सं० सां०का०नि० 2983 तारीख 21-7-1969
(8) अधिसूचना सं० सां०का०नि० 1122 तारीख 9-7-1976
(9) अधिसूचना सं० सां०का०नि० 1588 तारीख 28-9-1976

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th May, 1983

S.O. 2498.—The following draft of certain rules further to amend the Coir Industry Rules, 1954, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), is hereby published as required by Sub-section (1) of section 26 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called The Coir Industry (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coir Industry Rules, 1954—

(a) for rule 18 the following rule shall be substituted namely :—

"18. Accounts of the Board.—(1) The Board shall maintain accounts of income and expenditure as well as assets and liabilities relating to each year in the forms set out in the Schedule.

(2) The audited accounts of income and expenditure and of assets and liabilities together with the audit report thereon shall be submitted to the Central Government as soon as may be, after such accounts are audited and in any case, not later than seven months from the close of the year to which the accounts relate.

(3) The Accounts of income shall be shown under the following heads :—

(a) Moneys received under section 14 of the Act,
(b) Grants received from the Central Government under section 14A of the Act,
(c) Any other money received by the Board,
(d) Interest on investments,
(e) Excess of income over expenditure of the powerloom factory (Hindustan Coir),
(f) Excess of income over expenditure in showrooms and sales depots.

(4) Expenditure incurred in the year shall be shown under separate heads and sub-heads as given in the Schedule.";

(b) In the Schedule, for Forms 2 and 3, the following Forms shall be substituted, namely :—

FORM—2

[See rule 18(1)]

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT OF THE COIR BOARD SHOWROOMS AND SALES DEPOTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,——

Figures for previous year	Head of Expenditure	Schedule	Figures for current year	Figures for previous year	Income	Schedule	Figures for current year
Rs. P.			Rs. P.	Rs. P.			Rs. P.
	To Salaries	1			By commission on sales	5	
	To Commission to Managers of Showroom and Sales Depot.	2			By Miscellaneous receipts	6	
	To Insurance				By excess of expenditure over income.		
	To Rent						
	To Rates and Taxes						
	To Depreciation	3					
	To Deferred Revenue Expenditure written off.						
	To other charges	4					
	To Excess of income over expenditure						
	Total :						

FORM—3

[See rule 18(1)]

MANUFACTURING AND TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,——

Figures for the previous year	Expenditure	Figures for the current year	Figures for the previous year	Income	Figures for the current year
Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.		Rs. P.
	To Opening Stock			By cost of Finished goods transferred to Trading Account.	
	Raw Material				
	Dyes and Chemicals			**By Closing Stock**	
	Semi-finished goods			Raw Materials	
	Work in progress			Dye and Chemicals	
	Others			Semi finished goods	
	To Purchases			Work in progress.	
	Dyeing Charges			Others	
	Lubricants				
	Water and Electricity				
	Wages				
	Employees contribution to Provident Fund and Employees State Insurance				
	Bonus to Workers				
	Carriage Inwards				
	Depreciation				
	Building				
	Plant and Machinery				
	Tool etc.				

Figures for the previous year	Expenditure	Figures for the current year	Figures for the previous year	Income	Figures for the curren year
Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.		Rs. P.
	To Cost of finished goods transferred from Manufacturing Account			By Sales	
	To Opening Stock of finished goods			By Sales on Consignment account	
	To Gross profit to Profit and Loss Accounts			By Closing stock of finished goods	
				By gross loss transferred to Profit and Loss Account	
	Total				

FORM—4

[See rule 18(1)]

HINDUSTAN COIR, KALAVOOR

Profit and Loss Account For The Year Ended 31st March .....

Figures for the previous year	Head of Expenditure	Figures for the current year	Figures for the previous year	Head of Account	Figures for the current year
Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.		Rs. P.
	To Salaries and Allowances			By Gross profit transferred from Trading Account	
	To Travelling Allowance.				
	To Contribution to Provident Fund and Employees State Insurance				
	To Postage and Telegram			By Miscellaneous Receipts.	
	To Telephone				
	To Rates and Taxes				
	To Interest				
	To Insurance				
	To Repairs and Maintenance of Buildings				
	To Repairs and Maintenance Machinery				
	To Carriage Outwards				
	To Bank Charges				
	To Discount				
	To Advertisement Charges				
	To Stipend to Trainees				
	To Stationery and Printing				
	To Office Expenses				
	Depreciation				
	Furniture and Fittings etc.				
	Sundry expenses				
	Net Profit			Net Loss	
	Total				

FORM—5

[See rule 18(1)]

HINDUSTAN COIR, KALAVOOR

Balance Sheet as on 31st March,.....

Figures for the previous year	Liabilities	Figures for the current year	Figures for the previous year	Assets		Figures for the current year
Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.		Schedule	Rs. P.
	Capital					
	Balance as per last balance sheet			Fixed Assets	7	
				Current Assets		
	Profit and Loss Account			**Closing Stock**		
	Net Profit brought down from last balance sheet.			Raw Materials		
				Chemicals		
	Add net profit during the year			Semi finished goods work in progress		
	Loans from Government of India			Finished goods		
	Loans from Bank			Stock with the Showrooms		
	Current liabilities			**Sunday Debtors**		
	Sundry Creditors			Showrooms		
	Interest outstanding			Others		
	Deposits/advances			Stamps in hand		
	Other liabilities			Cash at Bank		
				Loans and Advances		
				Deposits recoverable		
				Advance to employee		
				Advance to others		
	Total					

FORM 6

[See rule 18(1)]

Income and Expenditure Account of the Coir Board for the year ended 31st March.....

Figures for the previous year	Head of Expenditure		Figures for the current year	Figures for the previous year	Head of Income		Figures for the current year
Rs. P.		Schedule	Rs. P.	Rs. P.		Schedule	Rs. P.
	To Administration	8			By Moneys received under Section 14 of he Coir Industry Act 1953		
	To Expansion of Home market						
	To Expansion of overseas Market						
	To Research (Science and Technology)				Less Cess Collection Charges		
	To Statistics Documentation and Data Base						

1	2	3	4	5
	To Marketing and Publicity	10	Grant received from Government of India under Section 14-A of Coir Industry Act, 1953	
	To Strengthening of National Level Training Institutions			
	To Export Regulation and Inspection-floor purchase price.			
	To Support for Co-operativisation in Coir (All India)		Other Receipts	1
	To Support for Training infrastructures			
	To Surveys and Studies		Interest on Investments Excess of expenditure over Income-Hindustan Coir.	
	To Establishment of Central Marketing Organisation			
	To Component Plan Scheduled Castes and Schedule Tribes	12		
	Others			
	Travelling Allowance to Members		Excess of Expenditures over Income 'Showrooms.	
	Depreciation on			
	Interest on loans			
	Excess of Income over expenditure Showrooms			

FORM-7

[See rule 18(1)]

Balance Sheet of the Coir Board as at 31st March,.....

Figures for the previous year	Liabilities	Schedule	Figures for the current year	Figures for the previous year	Assets	Schedule	Figures for the current year
Rs. P.			Rs. P	Rs. P			Rs. P.
	Capital				Fixed Assets	14	
	Balance as per last balance sheet				Investments		
	Coir Fund Account				Current Assets	15	
	Opening Balance				Closing Stock		
					Stock with showrooms		
	Less : Excess of income over expenditure during the year				Sundry Debtors	16	
					Showrooms		
					Hindustan Coir		
					Others		
	Loan from Government of India				Stamp in hand		
					Cash in hand		

1	2
Current Liabilities	
Sundry creditors	Cash at Bank in current account.
Interest outstanding	Cash at Bank in deposit account
Deposits/advances	
Other liabilities	
	Loans and Advances
	Deposits recoverable
	Advance to employees
	Advance to others
	Coir Fund Account
	Opening balance
	Add : Excess of expenditure over income.
Total	

NOTE

Coir Industry Rules, 1954 published vide Notification No. S.R.O. 2226 dated 6-7-1954 Gazette of India Extraordinary Part II Section 3 Pages 1109 to 1116 subsequently amended by :

(1) Notification No. S.R.O. 973 dated 29-4-1955
(2) Notification No. S R O. 3669 dated 17-12-1955
(3) Notification No. S.R.O. 3983 dated 12-12-1955
(4) Notification No. S.R.O. 877 dated 9-4-1960
(5) Notification No. G.S R. 1088 dated 18-6-1963
(6) Notification No. S.O. 1744 dated 6-5-1967
(7) Notification No. S.O. 2983 dated 21-7-1969
(8) Notification No. G.S.R. 1122 dated 9-7-1976
(9) Notification No G.S.R. 1588 dated 28-9-1976

[F. No. 6(3)/79-ICC(COIR)]
S. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 21 मई, 1983

का० आ० 2499:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस० डब्ल्यू० एम० डी० से मोटवान (जी० सी० एम०) तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० एस० डब्ल्यू० एम० डी० से मोटवान (जी० सी० एम०) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं०	हे०	एआर ई	से०
मोटवान	227	0	20	80
	232	0	05	85

[सं० 12016/32/83-प्रो०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 21st May, 1983

S.O. 2499.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SWMD to Motwan (GCS) in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadoda (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WELL NO. SWMD TO MOT. (GCS)

State:Gujarat District:Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Motwan	227	0	20	80
	232	0	05	85

[No. 12016/32/83-Prod]

का० आ० 2500:—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सी०टी० एफ० कलोल तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम-1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देख-भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

विरमगाम से सी० टी० एफ० कलोल

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वे० नं०	हे०	आर०	सै०
आगोल	1519/1	0	12	60
	1518/1	0	01	87
	1520/पी	0	31	35
	1520/पी	0	05	55
	कार्ट ट्रैक	0	00	50
	1527/पी	0	10	50
	1526	0	00	40
	1525/1/ए	0	19	95
	1524/1	0	07	95
	1524/3	0	10	05
	1574	0	03	75
	1573	0	00	15
	1575	0	04	35
	1572	0	18	60
	1604	0	08	40
	1602	0	12	30
	1596	0	10	05
	1595/2	0	03	00
	1595/1	0	07	30
	1595	0	11	25
	1594	0	00	15
	1592	0	01	25
	1591	0	05	55
	1589	0	09	90
	कार्ट ट्रैक	0	00	45
	134	0	09	75
	133/1	0	08	30
	131	0	00	20
	132	0	06	50
	127	0	06	00
	125	0	03	37
	126	0	03	38
	125	0	05	10
	120	0	05	55
	119	0	21	90
	150	0	00	15
	151	0	10	95
	153	0	05	40
	154	0	05	55
	155/2	0	03	00
	155/1	0	00	90
	156	0	06	00
	158	0	09	75
	161/3	0	10	50
	162/1	0	11	85
	165/1	0	11	40
	165/2	0	00	15

[सं० 12016/41/83 प्रोड]

S.O. 2580.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF Kalol in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
AGOL	1519/1	0	12	60
	1518/1	0	01	87
	1520/P	0	31	33
	1520/P	0	05	55
	Cart track	0	00	50
	1527/P	0	10	50
	1526	0	00	40
	1525/1/A	0	19	95
	1524/1	0	07	95
	1524/3	0	10	05
	1574	0	03	75
	1573	9	00	15
	1575	0	04	55
	1572	00	18	60
	1604	0	08	40
	1602	00	12	50
	1596	0	10	05
	1595/2	0	03	00
	1595/1	0	07	50
	1593	0	11	25
	1594	0	00	15
	1592	0	01	25
	1591	00	05	55
	1589	0	09	90
	Cart track	0	00	45
	134	0	09	75
	133/2	0	08	30
	131	0	00	20
	132	0	06	50
	127	0	06	00
	125	0	03	37
	126	0	03	38
	123	0	05	10
	120	0	05	55
	119	0	21	90
	150	0	00	15
	151	0	10	95
	153	0	05	40
	154	0	05	55
	155/2	0	05	00
	155/1	0	00	90
	156	0	06	00
	158	0	09	75
	161/3	0	10	50
	162/1	0	11	85
	165/1	0	11	40
	165/2	0	00	15

[No. 12016/41/83-Prod.]

का०आ० 2051.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एम० टी० बी० से मोटवान–1 तक पट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधीकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एम० टी० बी० से मोटवान-1 तक पाईपलाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं०	हे०	आर०	से०
मोटवान	55	0	07	80
	52	0	07	80

[सं० ओ-12016/42/83-प्रोड]

S.O. 2501.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from MTB to Motwan-1 in Gujarat State pipeline should be held by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenince Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be head in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM MTB TO MOTWAN-1.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Motwan	55	0	07	80
	52	0	07	80

[No. O-12016/42/83-Prod]

का०आ० 2502.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सी० टी० एफ० कलोल तक पट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अत: अब पट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अनुसूची

विरमगाम से सी० टी० एफ० कलोल

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	ब्लाक नं०	हे०	आर०	सै०
रामनगर	कार्ट ट्रेक	0	00	75
	210	0	06	75
	211	0	18	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	90

[सं० 12016/50/83- प्रोड]

S.O. 2502.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF Kalol in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009),

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be head in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM VIRAMGAM TO CTF KALOL

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Ramnagar	Cart Track	0	00	75
	210	0	06	75
	211	0	18	00
	Cart Track	0	00	90

[No. 12016/50/83-Prod.]

का० आ० 2503.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 208 तारीख 6-12-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

विरमगाम से सी० टी० एफ कलोल तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : कडी

गांव	सर्वे०नं०	हे०	आर०	से०
वलावडी	कार्टट्रेक	0	00	75
	211	0	35	85
	209	0	27	75
	248	0	11	70
	कार्ट ट्रेक	0	04	20
	219	0	14	25
	222	0	09	60
	220	0	29	55
	221	0	13	20
	कार्ट ट्रेक	0	00	60

[सं० 12016/62/82-प्रोड]

S.O. 2503.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 208, dated 6-12-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 3 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after Considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Valavadi	Cart Track	0	00	75
	211	0	35	85
	209	0	27	75
	248	0	11	70
	Cart Track	0	04	20
	219	0	14	25
	222	0	09	60
	220	0	29	55
	221	0	13	20
	Cart Track	0	00	60

[No. 12016/62/82-Prod.]

नई दिल्ली, 23 मई, 1983

का० आ० 2504 .—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 215 तारीख 6-12-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः समक्ष प्रधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो

पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

सी० टी० एफ० कलोल से विरमगाम तक पाईपलाईन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टर	आर	सैन्टीयर
1	2	3	4	5
नानी कुमाद	105	0	51	15
	106	0	00	10
	107	0	15	30
	111	0	28	50
	112	0	04	35
	कार्ट ट्रेक	0	04	05
	100	0	25	20
	101	0	07	20
	99	0	25	65
	98	0	11	25
	81	0	16	65
	82	0	00	15
	83	0	00	75
	88	0	14	25
	90	0	31	95
	57	0	25	20
	58	0	36	45
	59	0	17	25
	52	0	09	30
	9	0	00	15
	51	0	10	35
	49	0	00	25
	50	0	11	45
	46	0	10	05
	47	0	10	35
	45	0	12	00
	42	0	10	80
	39	0	17	05
	38	0	05	80
	37	0	00	20
	36	0	03	00
	35	0	07	50
	34	0	08	40
	33	0	17	85
	32	0	08	40
	31	0	07	50
	30	0	07	50
	29	0	08	10
	28	0	02	55

[सं० 12016/56/82-प्रो०]

राजेन्द्र सिंह, निदेशक

S.O. 2504.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 215, dated 6-12-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1950 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decide to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from CTF Kalol to Viramgam

State : Gujarat District: Ahmedabad Taluka : Vira-Gam

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Nani Kumad	105	0	51	15
	106	0	00	10
	107	0	15	30
	111	0	28	50
	112	0	04	35
	Cart Track	0	04	05
	100	0	25	20
	101	0	07	20
	99	0	25	65

1	2	3	4	5
	98	0	11	25
	81	0	16	65
	82	0	00	15
	83	0	00	75
	88	0	14	25
	90	0	31	95
	57	0	25	20
	58	0	36	45
	59	0	17	25
	52	0	09	30
	9	0	00	15
	51	0	10	35
	49	0	00	25
	50	0	11	45
	46	0	10	05
	47	0	10	35
	43	0	12	00
	42	0	10	80
	39	0	17	05
	38	0	05	50
	37	0	00	20
	36	0	03	00
	35	0	07	50
	34	0	08	40
	33	0	17	85
	32	0	08	40
	31	0	07	50
	30	0	07	50
	29	0	08	10
	28	0	02	55

[No. 12016/56/82-Prod.]
RAJINDRA SINGH, Director

नई दिल्ली, 19 मई 1983

का० आ० 2505.—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० एफ० डी० जी० से कूप नं० 171 तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए हैं ;

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-2-82 से समाप्त कर दिया गया है ;

अतः अब पेट्रोलियम पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

एफ० डी० जी० से कूप नं० 171 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का. आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य-समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग	उमरवाडा	3578	16-10-82	12-2-82

[सं० 12016/14/82-प्रोड-I]

New Delhi, the 19th May, 1983

S.O. 2505.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. Well No. FDG (220) to Well No. 171 in Ankleshwar oil field in Gujarat State;

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 15-2-82;

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. FDG to Well No. 171.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Umarwada	3578	16-10-82	15-2-82

[No. I20I6/I4/82-Prod-I]

नई दिल्ली, 20 मई, 1983

का० आ० 2506.—यत: भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य के मेहसाणा तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल स० एन० के० सी० वी० से एन के सी एन तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 31-3-81 से समाप्त कर दिया गया है ।

अत: अब पेट्रोलियम पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

एन० के० सी० वी० से एन० के० सी० एन तक पाइप लाइन

कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव का आ. सं.	भारत के राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग	तेलावी 3182	11-9-82	31-3-81

[सं० 12016/70/81-प्रोड]

New Delhi, the 20th May, 1983

S.O. 2506.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the right of user has been acquired in the lands specified in the Schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. NKCV to NKCN in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 31-3-81.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S. NKCV to NKCN

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Telavi	3182	11-9-82	31-3-81

[No. 12016/70/81 Prod.]

का० आ० 2507.—यत: भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां सलग्न अनुसूची मे निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य के मेहसाणा तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि मे व्यधन स्थल सं० एन० के० डब्लू० से जी० जी० एस० एन के० 1 तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (i) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 2-6-80 से समाप्त कर दिया गया है ।

अत: अब पैट्रोलियम पाइपलाईन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

एन० के० डब्लू से जी जी एस एन के 1 तक पाइप लाइन

कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम (पैट्रोलियम विभाग)	गाव	का. आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय	तेलावी	3183	11-9-82	2-6-80

[सं० 12016/70/81-प्रोड-II]

S.O. 2507 .—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the right of user has been acquired in the lands specified in the Schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. NKW to GGS NK1 in Mehsana oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 2-6-80.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S. NKW to GGS NK-1

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Telavi	3183	11-9-82	2-6-80

[No. 12016/70-/81-Prod. II]

नई दिल्ली, 21 मई, 1983

का० आ० 2508.—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० डब्लू० एम० डी० (वेस्ट मोटवान) से कूप नं० डब्लू० एम० बी० तक पट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (i) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 21-7-82 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम 1963, के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

डब्लू० एम० डी० (वेस्ट मोटवान) से कूप नं० डब्लू० एम० बी० तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का. आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	कलम	3580	16-10-82	21-7-82

[सं० 12016/18/82/प्रोड I]

New Delhi, the 21 May, 1983

S. O. 2508.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the right of user has been acquired in the lands specified in the Schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. WMD (West Motwan) to Well No. WMB in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 21-7-82.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. WMD (West Motucan) to Well No. WMB

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Kalam	3580	16-10-82	21-7-82

[No. 12016/18/82-Prod. I]

का०आ० 2509.—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार

का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० डब्लू० एम० डी० से डब्लू एम० बी० तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (i) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 21-7-82 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूकित करते हैं ।

अनुसूची

डब्लू०एम०डी० से डब्लू०एम०बी० तक पाइप लाइन कार्य समाप्ती

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग	वालनेर	3531	16-10-82	21-7-82

[सं० 12016/18/82/प्रोड०-II]

S.O. **2509**.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minterals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the right of user has been acquired in the lands specified in the Schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. WMD to WMB in Anklesh-war oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 21-7-82.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby noitfies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. WMD to WMB

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Walner	3581	16-10-82	21-7-82

[No. 12016/18/82-Prod. II]

नई दिल्ली, 23 मई, 1983

का०आ० 2510.—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० कूप नं० 1 से एम० पी० एच० तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (i) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 18-8-82 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

कूप नं 1 से एम० पी० एच० तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	हजान	2149	12-6-82	18-8-82

[सं० 12016/61/81/प्रोड I]

New Delhi, the 23rd May, 1983

S.O. **2510**.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the right of user

has been acquired in the lands specified in the Schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. Well No. 1 to MPH in Ankleshwar oi field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 18-8-82.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S. Well No. 1 to MPH

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Hajat	2149	12-6-82	18-8-82

[No. 12016/61/81-ProdI-]

का०आ० **2511**—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० कूप न० 122 से 21 तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (i) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 10-1-83 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

कूप न० 122 से 21 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का. आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग)	हजात	2148	12-6-82	10-1-83

[सं० 12016/61/81/प्रोड II].

S.O.2511.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the right of user has been acquired in the lands specified in the Schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. Well No. 122 to 21 in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 10-1-83.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. Well No. 122 to 21

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Hajat	2148	12-6-82	10-1-83

[12016/61/81—Prod. II]

का० आ० सं० **2512**.— यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाणा तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० एम० ई० पी० से सोकासन जीजी एस II तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (i) की धारा (j) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 14-5-81 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

एस० ई० पी० से सोकासन जीजी एस० II तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का. आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग)	कोचवा	3199	11-9-82	14-5-81

[सं० 12016/72/81/प्रोड-I]

S.O. 2512—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the right of User, has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SEP to Sobhasan GGS II in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 14-5-81.

Now therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SEP to Sobhasan GGSII

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Kochva	3199	11-9-82	14-5-81

[No. 12016/72/81 Prod-I]

का० आ० 2513—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाणा तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यक्त स्थल सं० एस० ई० एम० से सोकासन जी० जी० एस० तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (i) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 28-12-80 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

एस० ई० एम० सोथासन से जी० जी०एस० तक पाइपलाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम (पैट्रोलियम विभाग)	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	जगुदन	3185	11-9-82	28-12-80

[सं० 12016/72/81 प्रोड-II]

S.O. 2513—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Mineranls Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the right of user has been acquired in the lands specified in the Schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SEM to SOB GGS in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 28-12-80.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S. SEM to SOB GGS.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Jagudan	3185	11-9-82	28-12-80

[No. 12016/72/81 Prod-II]

नई दिल्ली, 24 मई, 1983

का० आ० 2514—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० डब्ल्यू० एम० एम० से एम० टी० बी० तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (i) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 24-11-82 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है।

अनुसूची

डब्ल्यू० एम० एम० से एम० टी० बी० तक पाइपलाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का. आ सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग)	कलम	344	15-1-83	24-11-82

[सं० 12016/25/82 प्रौड़]

New Delhi, the 24th May, 1983

S.O. 2514—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the right of user has been acquired in the lands specified in the Schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. WMM to MTB in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 24-11-82.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. WMM to MTB

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Kalam	344	15-1-83	24-11-82

[No. 1216/025/82 Prod.]

नई दिल्ली, 25 मई, 1983

का० आ० 2515—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० कूप नं० 81 से बूथ नं० 2 तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 10-1-83 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

कूप नं० 81 से बूथ नं० 2 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग)	सरथाण	3673	30-10-82	10-1-83

[सं० 12016/60/81/प्रोड० I]

New Delhi, the 25th May, 1983

S.O.....Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. well no 81 to Booth no 2 in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 10-1-83.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FROM D.S. WELL NO 81 TO BOOTH NO 2

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy	Sarthan	3673	30-10-82	10-1-83

[No. 12016/60/81-Prod I]

नई दिल्ली 28 मई, 1983

का०आ० 2516.—यत: भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० कूप नं० 122 से 21 तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में उपर्युक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 10-1-83 से समाप्त कर दिया गया है ।

अत: अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

कूप नं० 122 से 21 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ती

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	अंकोल	1914	29-5-82	10-1-83

[सं० 12016/59/81 प्रोड-I]

ह० अपठनीय

गुजरात के लिए नियमान्तर्गत समक्ष प्राधिकारी

New Delhi, the 28th May, 1983

S.O. No. 2516 Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transfort of petroleum from d.s. Well no 122 to 21 in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of sectinn 7 of the said Act on 10-1-83.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FROM D.S. Well no. 122 to 21

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Ministry of Energy (Dept. of Petroleum)	Adol	1914	29-5-82	10-1-83

[No. 12016/59/81-Proad I]

COMPETENT AUTHORITY UNDER THE ACT FOR GUJARAT

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 1983

का० आ० 2517.—जबकि केन्द्रीय सरकार भूतपूर्व श्रम मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या का० आ० 1001 दिनांक 6 मार्च, 1979 के द्वारा उप सचिव, प्रभारी श्रम कल्याण, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, को कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क के अधीन गठित न्यासी बोर्ड में एक न्यासी की हैसियत से नियुक्त किया था;

और जबकि उपर्युक्त न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थिति की अनुमति लिए बिना न्यासी बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं हुआ और कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के पैरा 6 के अधीन न्यासी नहीं रहा;

और जबकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त न्यासी के बोर्ड की ऐसी बैठकों से अनुपस्थित रहने के समुचित आधार थे ,

अतः, अब, कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के पैरा 6 के परन्तुक के साथ पठित कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उप सचिव, प्रभारी श्रम कल्याण, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता को न्यासधारिता को, भारत सरकार भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 2151, दिनांक 10 जुलाई, 1978 में क्रम सं० 7 पर, एतद्द्वारा प्रत्यर्पित करती है।

[सं० 7 (3)/80-प्रशा०-1 (भ० नि०)]

श्रीमती कु० सूद, निदेशक

(Department of Coal)

New Delhi, the 19th May, 1983

S.O. 2517.—Whereas the Central Government in the erstwhile Ministry of Labour appointed, vide its Notification No. S.O. 1001, dated the 6th March, 1979, Deputy Secretary, Incharge of Labour Welfare Labour Department, Government of West Bengal as a trustee on the Board of Trustees constituted under Section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948);

And whereas the said trustee failed to attend three consecutive meetings of the Board of Trustees without obtaining leave of absence from the Chairman of the Board and ceased to be a trustee under paragraph 6 of the Coal Mines Provident Fund Scheme;

And whereas the Central Government is satisfied that there were reasonable grounds for the absence of the said trustee from such meetings of the Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), read with the proviso to paragraph 6 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, the Central Government hereby restores the trusteeship of Deputy Secretary, Incharge of Labour Welfare, Labour Department, Government of West Bengal, Calcutta against serial number 7 of the Notification of the Government of India in the erswhile Ministry of Labour, No. S.O. 2151, dated the 10th July, 1978.

[No. 7(3)/80-Adm. I(PF)]

Smt. K. SOOD, Director.

नई दिल्ली, 27 मई, 1983

का० आ० 2518.—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन) की अधिसूचना का० नि० आ० सं० 1932 तारीख 10 जून, 1957, भूतपूर्व इस्पात खान और भारी इंजीनियरी मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1628 तारीख 8 मई, 1964, भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2836 तारीख 11 अगस्त, 1964 और भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3502 तारीख 4 नवम्बर, 1965 को अधिक्रांत करते हुए, इसने उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को, उक्त अधिनियम की उस धारा के प्रयोजन के लिए जो कि अनुसूची के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची, बिहार की अधिकारिता के भीतर जाने वाले क्षेत्र को तावत, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

अनुसूची

क्र० सं०	अधिनियम की धारा	संक्षेप में समनुदेशन की प्रकृति	सक्षम प्राधिकारी के रूप मे नियुक्त व्यक्ति का पदाभिधान और कार्यालय पता
1	2	3	4
1.	4(3)	पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण, खुदाई, प्रबंध निदेशक बोर करना आदि	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची
		निदेशक	यथोक्त
		महाप्रबन्धक	,,
		अपर मुख्य, भू-विज्ञान और ड्रिलिंग	,,

1	2	3	4
		उप मुख्य भू-विज्ञान	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची
		अधीक्षण भू-विज्ञानी	,,
		ज्येष्ठ भू-विज्ञानी	,,
		भू-विज्ञानी	,,
		ज्येष्ठ उप अधीक्षक ड्रिलिंग	,,
		उप अधीक्षक ड्रिलिंग	,,
		ज्येष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी	,,
		सर्वेक्षण अधिकारी	,,
		प्रबंध निदेशक	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि०, रांची
		मुख्य, भू-विज्ञान और ड्रिलिंग	यथोक्त
		अपर मुख्य भू-विज्ञान और ड्रिलिंग	,,
		प्रादेशिक निदेशक	,,
		उप मुख्य, भू-विज्ञान	,,
		अधीक्षण भू-विज्ञानी	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि०, रांची
		उप-अधीक्षण भू-विज्ञानी	,,
		ज्येष्ठ भू-विज्ञानी	,,
		भू-विज्ञानी	,,
		अधीक्षक, ड्रिलिंग	,,
		ज्येष्ठ उप अधीक्षक ड्रिलिंग	,,
		उप अधीक्षक, ड्रिलिंग	,,
		सर्वेक्षण अधिकारी	,,
		महा निदेशक	भारतीय भू-विज्ञानी सर्वेक्षण, कलकत्ता
		उप-महानिदेशक	यथोक्त
		निदेशक	,,
		प्रबंध निदेशक	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि०, नागपुर
		निदेशक	यथोक्त
		मुख्य भू-विज्ञानी	,,
		उप मुख्य भू-विज्ञानी	,,
2. 6	धारा 4(3) के अधीन किए गए नुकसान के लिए प्रतिकर	प्रबंध निदेशक	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, रांची
		निदेशक	यथोक्त
		महाप्रबंधक	,,
		अपर मुख्य भू-विज्ञान और ड्रिलिंग	,,
		मुख्य, राजस्व	,,
		उप मुख्य (राजस्व)	,,
		सहायक मुख्य (राजस्व)	,,
3. 8(2)	आक्षेप की सुनवाई	कोयला, नियंत्रक	कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता।

1	2	3	4	
4.	12	भूमि का कब्जा लेने के लिए शक्ति	प्रबंध निदेशक	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, राची
			निदेशक	यथोक्त
			महाप्रबंधक	,,
			मुख्य, राजस्व	,,
			उप मुख्य, राजस्व	,,
			ज्येष्ठ राजस्व अधिकारी	,,
			राजस्व अधिकारी	,,
			सहायक राजस्व अधिकारी	,,
5.	13(6)	उस नुकसान के लिए प्रतिकर, जिसके लिए अधिनियम में उपबन्ध नहीं किया गया है।	प्रबंध निदेशक	,,
			निदेशक	,,
			महाप्रबंधक	,,
			मुख्य राजस्व	,,
			उप मुख्य (राजस्व)	,,
			सहायक मुख्य (राजस्व)	
			ज्येष्ठ राजस्व अधिकारी	,,
6.	22	किसी संपत्ति पर प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति	प्रबंध निदेशक	,,
			निदेशक	,,
			महाप्रबंधक	,,
			अपर मुख्य भू-विज्ञान और ड्रिलिंग	,,
			मुख्य, राजस्व	,,
			उप मुख्य (राजस्व)	,,
			सहायक मुख्य (राजस्व)	,,
			ज्येष्ठ राजस्व अधिकारी	,,
			राजस्व अधिकारी	,,

[सं० 19/41/78 सी० एल०]

New Delhi, the 27th May, 1983

S.O. 2518.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel) S.R.O. No. 1932 dated the 10th June, 1957, in the late Ministry of Steel Mines and Heavy Engineering (Department of Mines and Metals) S.O. No. 1628 dated the 8th May, 1964, in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines and Metals) S.O. No. 2836 dated the 11th August, 1964 and in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines and Metals) S.O. No. 3502 dated the 4th November, 1965, the Central Government hereby appoints each of the persons specified in column 4 of the Schedule hereto annexed to be the competent authority for the purpose of such of section of the said Act as is specified against him in the corresponding entry in the column 2 thereof, in respect of the areas falling within the jurisdiction of the Central Coalfields Ltd., Ranchi, Bihar.

Sl. No.	Section of the Act	Nature of assignment in brief	Designation and official address of the person appointed as competent authority	
1	2	3	4	
1	4(3)	Prospecting, survey, dig, bore, etc.	Managing Director	Central Coalfields Limited, Ranchi.
			Directors	-do-
			General Managers	-do-

1	2	3	4	
			Additional Chief of Geology and Drilling	Central Coalfields Limited, Ranchi
			Deputy Chief of Geology	-do-
			Superintending Geologists	-do-
			Deputy Superintending Geologists	-do-
			Senior Geologists	-do-
			Geologists	-do-
			Senior Deputy Drilling Superintendants	-do-
			Deputy Drilling Superintendents	-do-
			Senior Survey Officers	-do-
			Survey Officers	-do-
			Managing Director	Central Mine Planning and Design Institute Limited, Ranchi.
			Chief of Geology and Drilling	-do-
			Additional Chief of Geology and Drilling	-do-
			Regional Directors	-do-
			Deputy Chief of Geology	-do-
			Superintending Geologists	-do-
			Deputy Superintending Geologists	-do-
			Senior Geologists	-do-
			Geologists	-do-
			Drilling Superintendents	-do-
			Senior Deputy Drilling Superintendents	-do-
			Deputy Drilling Superintendent	-do-
			Survey Officers	-do-
			Director General	Geological Survey of India, Calcutta.
			Deputy Director General	-do-
			Directors	-do-
			Managing Director	Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur.
			Directors	-do-
			Chief Geologist	-do-
			Deputy Chief Geologists	-do-
2	6	Compensation for damage done under section 4(3)	Managing Director	Central Coalfields Limited, Ranchi.
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Additional Chief of Geology and Drilling	-do-
			Chief of Revenue	-do-
			Deputy Chief (Revenue)	-do-
			Assistant Chief (Revenue)	-do-
3	8(2)	Hearing of objection	Coal Controller	Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta.

1	2	3	4	
4	12	Power to take possession of land	Managing Director	Central Coalfileds Ltd., Ranchi.
			Directors. General Manager	-do-
			Chief of Revenue	-do-
			Deputy Chief of Revenue	-do-
			Assistant Chief (Revenue)	-do-
			Senior Revenue Officers	-do-
			Revenue Officers	-do-
			Assistant Revenue Officers	-do-
5	13(6)	Compensation for damages not provided in the Act	Managing Director	-do-
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Chief of Revenue	-do-
			Deputy Chief (Revenue)	-do-
			Assistant Chief (Revenue)	-do-
			Senior Revenue Officers	-do-
6	22	Power to enter and inspect any property.	Managing Director	-do-
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Additional Chief of Geology and Drilling	-do-
			Chief of Revenue	-do-
			Deputy Chief (Revenue)	-do-
			Assistant Chief (Revenue)	-do-
			Senior Revenue Officers	-do-
			Revenue Officers	-do-

[No. 19/41/78-CL]

का० आ० 2519 .—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1301, तारीख 9 अप्रैल, 1975 का० आ० 778, तारीख 31-1-1976 को अधिक्रान्त करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को, उक्त अधिनियम की उस धारा के प्रयोजन के लिए जो कि अनुसूची के स्तंभ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट है, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों की बाबत, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

अधिसूचना

क्र० सं०	अधिनियम की धारा	संक्षेप में समनुदेशन की प्रकृति	सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति का पदाभिधान और कार्यालय पता	
1	2	3	4	
1.	4(3)	पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण, खुदाई, बोर, करना आदि	प्रबंध निदेशक	वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, नागपुर
			निदेशक	यथोक्त
			महा प्रबंधक	यथोक्त
			अधीक्षण भू-विज्ञानी	यथोक्त
			ज्येष्ठ भू-विज्ञानी	यथोक्त
			भू-विज्ञानी	यथोक्त
			उप अधीक्षक, ड्रिलिंग	यथोक्त

1	2	3	4	
			ज्येष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी	वैस्टर्न कोलफील्डस, लिमिटेड
			सर्वेक्षण अधिकारी	,,
			प्रबंध निदेशक	,,
			मुख्य, भू-विज्ञान और ड्रिलिंग	सेंट्रल-माइन पलानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची
			अपर मुख्य, भू-विज्ञान ड्रिलिंग	यथोक्त
			प्रादेशिक निदेशक	,,
			उप प्रधान, भू-विज्ञान	,,
			अधीक्षण भू-विज्ञानी	,,
			उप अधीक्षण भू-विज्ञानी	,,
			ज्येष्ठ भू-विज्ञानी	,,
			भू-विज्ञानी	,,
			अधीक्षक, ड्रिलिंग	,,
			ज्येष्ठ उप अधीक्षक, ड्रिलिंग	,,
			उप अधीक्षक, ड्रिलिंग	,,
			सर्वेक्षण अधिकारी	,,
			महा निदेशक	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता
			उप महानिदेशक	,,
			निदेशक	,,
			प्रबंध-निदेशक	मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन, लिमिटेड, नागपुर
			निदेशक	यथोक्त
			मुख्य, भू-विज्ञानी	,,
			उप मुख्य, भू-विज्ञानी	,,
2. 6	धारा 4(3) के अधीन किए गए नुकसान के लिए प्रतिकर	प्रबंध निदेशक		वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, नागपुर
			निदेशक	यथोक्त
			महा प्रबंधक	,,
			अपर मुख्य भू-विज्ञान और ड्रिलिंग	,,
			मुख्य राजस्व	,,
			उप मुख्य, (राजस्व)	,,
			सहायक मुख्य, (राजस्व)	,,
3. 8(2)	आक्षेप की सुनवाई	कोयला नियंत्रक		कोयला नियंत्रक 1 काउंसिल हाउस कलकत्ता
4. 12	भूमि का कब्जा लेने की शक्ति	प्रबंध निदेशक		वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर
			निदेशक	यथोक्त
			अपर मुख्य कार्मिक प्रबंध (प्रशासन)	यथोक्त
			उप संपदा प्रबंधक	यथोक्त
			सहायक संपदा प्रबंधक	यथोक्त

1	2	3	4	
		ज्येष्ठ राजस्व अधिकारी	वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,	नागपुर
		राजस्व अधिकारी	यथोक्त	
		सहायक राजस्व अधिकारी	यथोक्त	
5.	13(6)	उस नुकसान के लिए प्रतिकर जिसके लिए अधिनियम उपबंध नहीं किया गया है।	प्रबंध निदेशक	वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर
			निदेशक	यथोक्त
			महाप्रबंधक	यथोक्त
			अपर मुख्य कार्मिक प्रबन्धक	यथोक्त
			उप संपदा प्रबंधक	यथोक्त
			सहायक संपदा प्रबंध	यथोक्त
			ज्येष्ठ राजस्व अधिकारी	यथोक्त
6.	22	किसी संपत्ति पर प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति	प्रबंध निदेशक	यथोक्त
			निदेशक	यथोक्त
			महाप्रबंधक	यथोक्त
			अपर मुख्य कार्मिक प्रबंधक (प्रशासन)	यथोक्त
			उप संपदा प्रबंधक	यथोक्त
			क्षेत्र योजना अधिकारी	यथोक्त
			ज्येष्ठ राजस्व अधिकारी	यथोक्त
			राजस्व अधिकारी	यथोक्त

[सं० 19/41/78-सी एल]

S.O. 2519.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) S.O. 1301 dated the 9th April, 1975 S.O. 778 dated 31-1-1976 the Central Government hereby appoints each of the persons specified in column 4 of the Schedule hereto annexed to be the competent authority for the purpose of such of the section of the said Act as is specified against his name in the corresponding entry in column 2 thereof in respect of the areas falling within the jurisdiction of the western Coalfields Ltd., Nagpur, Maharashtra.

SCHEDULE

Sl. No.	Section of the Act	Nature of assignment in brief	Designation & official address of the person appointed as competent authority	
1	2	3	4	
1	4(3)	Prospecting, survey, dig, bore, etc.	Managing Director.	Western Coalfields Limited, Nagpur.
			Directors.	-do-
			General Managers.	-do-
			Superintending Geologist	-do-
			Senior Geologist	-do-
			Geologist	-do-
			Deputy Drilling Superintendent,	-do-
			Senior Survey Officer	-do-
			Survey Officer.	-do-
			Managing Director.	Central Mine Planning and Design Institute Limited, Ranchi.
			Chief of Geology and Drilling.	
			Additional Chief of Geology and Drilling.	-do-

1	2	3	4	
			Regional Directors.	Central Mine Planning and Design Institute Limited, Ranchi.
			Deputy Chief of Geology	
			Superintending Geologists.	-do-
			Deputy Superintending Geologists	-do-
			Senior Geologists	-do-
			Geologists	-do-
			Drilling Superintendents	-do-
			Senior Deputy Drilling Superintendents	-do-
			Deputy Drilling Superintendents	-do-
			Survey Officers	-do-
			Director General	Geological Survey of India, Calcutta.
			Deputy Director General	-do-
			Directors	-do-
			Managing Director	Mineral Exploration Corporation, Ltd, Nagpur.
			Director	-do-
			Chief Geologist	-do-
			Deputy Chief Geologists	-do-
2	6	Compensation for damage done under section 4(3).	Managing Director	Western Coalfields Limited, Nagpur.
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Additional Chief of Geology and Drilling	-do-
			Chief of Revenue	-do-
			Deputy Chief (Revenue)	-do-
			Assistant Chief (Revenue)	-do-
3	8(2)	Hearing of objection.	Coal Controller	Coal Controller, 1, Council House, Calcutta.
4	12	Power to take possession of land.	Managing Director	Western Coalfields Limited, Nagpur.
			Directors	
			General Managers	-do-
			Additional Chief Personnel Manager (Administration)	-do-
			Deputy Estate Manager	-do-
			Assistant Estate Manager	-do-
			Senior Revenue Officers	-do-
			Revenue Officers	-do-
			Assistant Revenue Officers	-do-
5	13(6)	Compensation for damage not provided in the Act.	Managing Director	Western Coalfields Limited, Nagpur.
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Additional Chief Personnel Manager (Administration)	-do-
			Deputy Estate Manager	-do-
			Assistant Estate Manager	-do-
			Senior Revenue Officer	-do-

1	2	3	4	
6	22	Power to enter and inspect any property.	Managing Director	Western Coalfields Ltd. Nagpur.
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Additional Chief Personnel Manager (Administration)	-do-
			Deputy Estate Manager	-do-
			Assistant Estate Manager	-do-
			Area Planning Manager	-do-
			Senior Revenue Officer	-do-
			Revenue Officer	-do-

[No. 19/41/78-CL]

का०आ० 2520.—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को, उक्त अधिनियम की उस धारा के प्रयोजन के लिए, जो कि अनुसूची के तत्स्थानी प्रविष्टि में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट है, ईस्टर्न, कोल फील्ड्स लि० सेंक्टोरिया, बर्दवान, पश्चिमी, बंगाल की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र की बाबत, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

अनुसूची

क्रम सं०	अधिनियम की धारा	संक्षेप में समनुदेशन की प्रकृति	सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति का पदनाम और कार्यालय का पता	
1	2	3	4	
1.	4(3)	पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण खुदा बोर करना आदि,	प्रबंध निदेशक	ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, सेंक्टोरिया
			निदेशक	यथोक्त
			महा प्रबंधक	यथोक्त
			अधीक्षका भू-विज्ञानी	यथोक्त
			ज्येष्ठ भू-विज्ञानी	यथोक्त
			भू-विज्ञानी	यथोक्त
			उप-मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी	यथोक्त
			ज्येष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी	यथोक्त
			सर्वेक्षण अधिकारी	यथोक्त
			प्रबंधक निदेशक	सेंट्रल माइन, प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि० रांची
			मुख्य भू-विज्ञान और ड्रिलिंग	यथोक्त
			अपर मुख्य, भू-विज्ञान और ड्रिलिंग	यथोक्त
			प्रादेशिक निदेशक	यथोक्त
			उप मुख्य-भू-विज्ञान	यथोक्त
			अधीक्षक भू-विज्ञानी	यथोक्त
			ज्येष्ठ भू-विज्ञानी	यथोक्त
			भू-विज्ञानी	यथोक्त
			अधीक्षक ड्रिलिंग	यथोक्त
			ज्येष्ठ उप अधीक्षक ड्रिलिंग	यथोक्त
			उप-अधीक्षक ड्रिलिंग	यथोक्त
			सर्वेक्षण अधिकारी	यथोक्त

1	2	3	4
		महा निदेशक	भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता
		उप महानिदेशक	
		निदेशक	यथोक्त
		प्रबंध निदेशक	मिनरल, एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि०, नागपुर
		निदेशक	मिनरल, एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि० नागपुर
		मुख्य भू-विज्ञानी	यथोक्त
		मुख्य भू-विज्ञानी	यथोक्त
2. 6	धारा 4(3) के अधीन किए नुकसान के लिए प्रतिकर	प्रबंध निदेशक	ईस्टर्न कोलफील्ड्स
		निदेशक	सेक्टोरिया, जिला बर्दवान
		महाप्रबंधक	यथोक्त
		अधीक्षण, भू-विज्ञानी	यथोक्त
		विभाग का प्रधान (भूमि और राजस्व)	यथोक्त
		भूमि और राजस्व अधिकारी	यथोक्त
3. 8(2)	आक्षेप की सुनवाई	कोयला नियन्त्रक	कोयला नियंत्रक 1, काऊंसिल हाउस, कलकत्ता
4. 12	भूमि का कब्जा लेने की शक्ति	प्रबंध निदेशक	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, सेक्टोरिया जिला, बर्दवान
		महा प्रबंधक	यथोक्त
		मुख्य भूमि, राजस्व और सर्वेक्षण परियोजना अधिकारी	यथोक्त
		उप-मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी	यथोक्त
		ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, सेंक्टोरिया जिला, बर्दवान ।	
		ज्येष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी	यथोक्त
		सर्वेक्षण अधिकारी	यथोक्त
5. 13(6)	उन नुकसान के लिए प्रतिकर जिसके लिए अधिनियम उपबंध में नहीं किया गया है ।	प्रबंध निदेशक	यथोक्त
		निदेशक	यथोक्त
		महाप्रबंधक	यथोक्त
		मुख्य भूमि, राजस्व और सर्वेक्षण परियोजना अधिकारी	यथोक्त
			यथोक्त
6. 22	किसी संपत्ति पर प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति ।	प्रबंध निदेशक	यथोक्त
		निदेशक	यथोक्त
		महा प्रबंधक	यथोक्त
		भूमि, राजस्व और सर्वेक्षण विभाग का प्रधान	यथोक्त
			यथोक्त
		क्षेत्र प्रबंधक (संक्रिया)	यथोक्त
		उप मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी	यथोक्त
		ज्येष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी	यथोक्त

[सं० 19/41/78-सी० एल०]

S.O. 2520.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby appoints each of the persons specified in column 4 of the Schedule (annexed) hereto to be the competent authority for the purpose of such of the section of the said Act as is specified against his name in the corresponding entry in column 2 thereof, in respect of the areas falling within the jurisdiction of the Eastern Coalfields Ltd., Sanctoria, Burdwan, West Bengal

SCHEDULE

Sl. No.	Section of the Act.	Nature of assignment in brief	Designation & official address of the person appointed as competent authority	
1	2	3	4	
1	4(3)	Prospecting, Survey, dig, bore, etc.	Managing Director	Eastern Coalfields Limited Sanctoria, District Burdwan.
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Superintending Geologist	-do-
			Senior Geologist	-do-
			Geologists	-do-
			Deputy Chief Survey Officers	-do-
			Senior Survey Officers	-do-
			Survey Officers	-do-
			Managing Director	Central Mine Planning and Design Institute Limited, Ranchi.
			Chief of Geology and Drilling	
			Additional Chief of Geology and Drilling	-do-
			Regional Directors	-do-
			Deputy Chief of Geology	-do-
			Superintending Geologists	-do-
			Deputy Superintending Geologists	
			Senior Geologists	-do-
			Geologists	-do-
			Drilling Superintendents	-do-
			Senior Deputy Drilling Superintendents	-do-
			Deputy Drilling Superintendents	-do-
			Survey Officers	-do-
			Director General	Geological Survey of India Calcutta
			Deputy Director General	-do-
			Directors	-do-
			Managing Director	Mineral Exploration Corporation Ltd. Nagpur.
			Director	-do-
			Chief Geologist	-do-
			Deputy Chief Geologists	-do-
2	6	Compensation for damage done under section 4(3)	Managing Director	Eastern Colafields Limited, Sanctoria District, Burdwan.
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Superintending Geologist	-do-
			Head of the Department (Land & Revenue)	-do-
			Land and Revenue Officer	-do-
3	8(2)	Hearing of objection.	Coal Controller	Coal Controller, 1, Council House, Calcutta.

1	2	3	4	
4	12	Power to take possession of land.	Managing Director	Eastern Coalfield Limited, Sanctoria District, Burdwan.
			Director	
			Managing Director	-do-
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Head of Land, Revenue and Survey	-do-
			Project Officer	-do-
			Deputy Chief Survey Officer	-do-
			Senior Survey Officer	-do-
			Survey Officers	-do-
5	13(6)	Compensation for damage not provided in the Act.	Managing Director	-do-
			Directors	-do-
			General Manages	-do-
			Head of Land, Revenue and Survey	-do-
			Project Officer	-do-
6	22	Power to enter and inspect any property.	Managing Director	-do-
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Head of Department, Land Revenue and Survey	-do
			Area Managers (Operation)	-do-
			Deputy Chief Survey Officers	-do-
			Senior Survey Officers	-do-

[No. 19/41/78-CL]

का० आ० 2521—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची (उपाबद्ध) के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को, उक्त अधिनियम की उप धारा के प्रयोजन के लिए, जैसा कि अनुसूची के स्तंभ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद, बिहार की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र की बाबत, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

अनुसूची

क्रम सं०	अधिनियम की धारा	संक्षेप में समनुदेशन की प्रकृति	सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति का पदाभिधान और कार्यालय पता
1	2	3	4
1.	4(3)	पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण, खुदाई, बोर करना आदि	प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
		निदेशक	—यथोक्त—
		महाप्रबंधक	—यथोक्त—
		उप मुख्य, भू-विज्ञानी	—यथोक्त—
		अधीक्षण, भू-विज्ञानी	—यथोक्त—
		ज्येष्ठ भू-विज्ञानी	—यथोक्त—
		भू-विज्ञानी	—यथोक्त—
		उप मुख्य प्रबंधक सपदा (सर्वेक्षण)	—यथोक्त—
		ज्येष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी	—यथोक्त—
		सर्वेक्षण अधिकारी	—यथोक्त—

1	2	3	4
		प्रबंध निदेशक	सेन्ट्रल माइन्स प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड, रांची।
		मुख्य, भू-विज्ञान और ड्रिलिंग	—यथोक्त—
		प्रादेशिक निदेशक	—यथोक्त—
		अधीक्षण भू-विज्ञानी	—यथोक्त—
		उप अधीक्षण भू-विज्ञानी	—यथोक्त—
		ज्येष्ठ भू-विज्ञानी	—यथोक्त—
		भू-विज्ञानी	—यथोक्त—
		अधीक्षक, ड्रिलिंग	—यथोक्त—
		ज्येष्ठ उप अधीक्षक, ड्रिलिंग	—यथोक्त—
		उप अधीक्षक, ड्रिलिंग	—यथोक्त—
		सर्वेक्षण अधिकारी	—यथोक्त—
		महानिदेशक	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कलकत्ता।
		उपमहानिदेशक	—यथोक्त—
		निदेशक	—यथोक्त—
		प्रबंध निदेशक	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर
		निदेशक	—यथोक्त—
		मुख्य भू-विज्ञानी	—यथोक्त—
		उप मुख्य भू-विज्ञानी	—यथोक्त—
2. 6	धारा 4(3) के अधीन किए गए नुकसान के लिए प्रतिकर	प्रबंध निदेशक	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद,
		निदेशक	—यथोक्त—
		महाप्रबंधक	—यथोक्त—
		अपर मुख्य भू-विज्ञानी और ड्रिलिंग	—यथोक्त—
		उप मुख्य खनन इंजीनियर (संपदा)	—यथोक्त—
		प्रबंधक (संपदा)	—यथोक्त—
		उप प्रबंधक (संपदा)	—यथोक्त—
3. 8(2)	आक्षेप की सुनवाई	कोयला नियंत्रक	कोयला नियंत्रक 1. काउन्सिल हाउस, कलकत्ता
4. 12	भूमि का कब्जा लेने की शक्ति	प्रबंध निदेशक	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद।
		निदेशक	—यथोक्त—
		महाप्रबंधक	—यथोक्त—
		उप मुख्य खनन इंजीनियर (संपदा)	—यथोक्त—
		प्रबंधक संपदा	—यथोक्त—
		उप प्रबंधक (संपदा)	—यथोक्त—
		ज्येष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी	—यथोक्त—
		ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी	—यथोक्त—
5. 22	किसी संपत्ति पर प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति।	प्रबंध निदेशक	—यथोक्त—
		निदेशक	—यथोक्त—
		महाप्रबंधक	—यथोक्त—
		उप मुख्य खनन इंजीनियर (संपदा)	—यथोक्त—
		प्रबंधक (संपदा)	—यथोक्त—

1	2	3	4
		उप प्रबंधक (संपदा)	भारत कोकिंग कोल लि०, धनबाद
		क्षेत्र प्रबंधक (योजना)	—यथोक्त—
		क्षेत्र प्रबंधक (सकनीकी)	—यथोक्त—
		ज्येष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी	—यथोक्त—
		ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी	—यथोक्त—

[सं० 19/41/78-सी० एल०]

S.O. 2521.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby appoints each of the persons specified in column 4 of the Schedule (annexed) hereto to be the competent authority for the purpose of such of the section of the said Act as is specified against his name in the corresponding entry in column 2 thereof in respect of the areas falling within the jurisdiction of the Bharat Coking Coal Ltd., Dhanbad, Bihar.

SCHEDULE

Sl. No.	Section of the Act.	Nature of assignment in brief	Designation & official address of the person appointed as competent authority	
1	2	3	4	
1	4(3)	Prospecting, survey, dig, bore, etc.	Managing Director	Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad.
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Deputy Chief Geologist	-do-
			Superintendeing Geologist	-do-
			Senior Geologist	-do-
			Geologists	-do-
			Deputy Chief Manager Estate (Survey)	-do-
			Senior Survey Officer	-do-
			Survey Officer	-do-
			Managing Director	Central Mine Planning and Design Institute Limited, Ranchi.
			Chief of Geology and Drilling	
			Additional Chief of Geology and Drilling	-do-
			Regional Directors	-do-
			Deputy Chief of Geology	-do-
			Superintending Geologists	-do-
			Deputy Superintending Geologists	-do-
			Senior Geologists	-do-
			Geologists	-do-
			Drilling Superintendents	-do-
			Senior Deputy Drilling Superintendents	-do-
			Deputy Drilling Superintendents	-do-
			Survey Officers	-do-
			Director General	Geological Survey of India, Calcutta.
			Deputy Director General	-do-
			Directors	-do-
			Managing Director	Mineral Exploration Corporation, Ltd. Nagpur.
			Directors	-do-
			Chief Geologists	-do-
			Deputy Chief Geologists	-do-

1	2	3	4	
2	6	Compensation for damage done u/s. 4(3).	Managing Director	Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad.
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Additional Chief of Geology and Drilling	-do-
			Deputy Chief Mining Engineer (Estate)	-do-
			Manager (Estate)	-do-
			Deputy Manager (Estate)	-do-
3	8(2)	Hearing of objection.	Coal Controller	Coal Controller 1, Council House, Calcutta.
4	12	Power to take possession of land.	Managing Director	Bharat Coking Coal Limited Dhanbad
			Directors	
			General Managers	-do-
			Deputy Chief Mining Engineer (Estate)	-do-
			Manager Estate	-do-
			Deputy Manager (Estate)	-do-
			Senior Survey Officer	-do-
			Senior Administration Officer	-do-
5	22	Power to enter and inspect any property.	Managing Director	-do-
			Directors	-do-
			General Managers	-do-
			Deputy Chief Mining Engineer (Estate)	Bharat Coking Coal Limited Dhanbad.
			Manager (Estate)	-do-
			Deputy Manager (Estate)	-do-
			Area Manager (Planning)	-do-
			Area Manager (Technical)	-do-
			Senior Survey Officer	-do-
			Senior Administration Officer	-do-

[No. 19/41/78-CL]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

CORRIGENDA

New Delhi, the 27th May, 1983

S.O. 2522.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3631, dated the 11th October, 1982, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd October, 1982 :—

at page 3773 In 1st column

in line 37 for "124 (part), 1 6 (part), 127 (part)",

read "124 (part), 126 (part), 127 (part)",

in line 55 for "acquired in village Lachh anpur"

read "acquired in village Lachhmanpur",

in 2nd column

in line 48 for "Madhupur (Alhadnagar) Raka",

read "Madhupur (Alhadnagar), Rakas.";

in line 53 for "u/s 9(1) of the Coal Act and",

read "u/s 9(1) of the Coal Act) and";

at page 3774 In 1st column

in line 13 for "Jambubahali, Pabitapur and"

read "Jambubahali, Pabitrapur and".

[No. 19/95/81-CL]

का. आ. 2523.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 2885, तारीख 28 जुलाई, 1982 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 4763.39 एकड़ (लगभग) या 1927.65 हैक्टर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 4763.39 एकड़ (लगभग) या 1927.65 हैक्टर (लगभग) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

टिप्पण-1 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक का निरीक्षण, जिला मजिस्ट्रेट, ढेनकनाल (उड़ीसा) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण-2 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंधित है :—

"8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हैं, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसा भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते ।"

टिप्पण-3 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची
नातिदी ब्लाक
(तलचेर कोयला क्षेत्र)

ड्राइंग सं० राजस्व/90/82
तारीख 22-12-82
(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	पुलिस थाना	संख्यांक	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	दानरा	तलचेर	कोयला खान	24	ढेनकनाल	2093.39	पूर्ण
2.	कुचीनाली	,,	,,	13	,,	100.36	,,
3.	जम्बूबाहली	,,	,,	22	,,	486.62	,,
4.	बादाजोरवा	,,	,,	52	,,	1056.00	भाग
5.	महेन्द्रपुर	,,	,,	121	,,	271.65	पूर्ण
6.	चिंतामणिपुर	,,	,,	21	,,	28.93	,,
7.	नातिदी	,,	,,	83	,,	334.22	,,
8.	बोलापुर	,,	,,	92	,,	292.22	,,

कुल क्षेत्र : 4763.39 एकड़ (लगभग)
या 1927.65 हैक्टर (लगभग)

ग्राम दानरा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 1 से 5318 ग्राम कुचीनाली में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 1 से 272 ग्राम जम्बूबाहली में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 1 से 956 ग्राम बादाजोरदा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 1 से 605, 608 (भाग), 609 से 675, 676 (भाग), 677, 678 (भाग), 679 से 681, 682 (भाग), 685 (भाग), 686 (भाग), 689 (भाग), 885 (भाग), 889 (भाग), 890, 891 (भाग), 892 (भाग), 895 (भाग) 896 (भाग), 897 से 924, 925 (भाग), 926 (भाग), 978 (भाग), 979 (भाग), 980, 981 (भाग), 989 (भाग), 990 (भाग), 991 से 994, 995 (भाग), 996 से 1169, 1173, 1174 (भाग) 1175, 1176 (भाग), 1177 (भाग), 1178 से 1380, 1381 (भाग), 1382 से 1403, 1404 (भाग), 1405 से 1420, 1421 (भाग), 1422 (भाग), 1424 (भाग), 1426 (भाग), 1427 (भाग), 1432 (भाग), 1436 (भाग), 1437 (भाग), 1438 (भाग), 1439, 1440, 1441 (भाग), 1442 से 1445, 1446 (भाग), 1447 (भाग), 1448 (भाग), 1488 (भाग), 2214 (भाग), 2216 (भाग), 2217, 2218 (भाग), 2228 (भाग), 2229 से 2235, 2236 (भाग), 2237 से 2246, 2247 (भाग), 2248 (भाग), 2249 (भाग), 2251 (भाग), 2252, 2253, 2254 (भाग), 2262 (भाग), 2263 (भाग), 2271 (भाग), 2272 (भाग), 2430 (भाग), 2932, 2941, 2942, 2946, 2947, 2959, 2978, 2979, 2980, 2981 2982, 3297, 3298, 3324, 3325, 3326, 3357, 3358, 3359, 3385, 3387, 3421, 3422, 3427, 3428, 3430, 3431, 3432, 3434, 3435, 11/3437, 11/3438, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3458, 3459, 3462, 3463, 3468, 3470, 3473, 3496, 3526, 3527, 3530 और 3531.

ग्राम महेन्द्र पुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 1 से 442 ।

ग्राम चिन्तामणिपुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 1 से 58 ।

ग्राम नातिदी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 1 से 608 ।

ग्राम बोलापुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 1 से 278 ।

सीमा वर्णन

क—ख रेखा ग्राम दानरा की भागत: उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख—ग रेखा दानरा और कुचीनाली, नातिदी और बोलापुर ग्रामों की दक्षिण-पश्चिम सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग—घ रेखा बोलापुर महेन्द्र पुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा के और ग्राम बादाजोरदा की भागत: पश्चिमी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ—ङ रेखा ग्राम बादाजोरदा के प्लाट संख्यांक 2430 से होकर प्लाट संख्यांक 606 की उत्तरी सीमा के साथ साथ प्लाट संख्यांक 608, 682, 685, 686, 689, 678, 676, 885, 889, 891, 892, 896, 895, 926, 925, 978, 979, 981, 989, 990, 995, 1488, 1174, 1176, 1177, 1446, 1447, 1441, 1446, 1438, 1437, 1436, 1432, 1381, 1427 1426, 1421, 1422, 1404, 2214, 2216, 2218 2228, 2272, 2236, 2271, 2263, 2262, 2254, 2251, 2247, 2248 और 2249 से होकर जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ—च रेखा बादाजोरदा और जम्बूबाहली ग्रामों की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिंदु "च" पर मिलती है ।

च—छ रेखा ग्राम दानरा की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है ।

छ—क रेखा ग्रामा दानरा की भागत: उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती है और आरम्भिक बिंदु "क" पर मिलती है ।

[सं० 19/5/83-सी०एल०]

S.O. 2523.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S. O. 2885, dated the 28th July, 1982, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 4763.39 acres (approximately) or 1927.65 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the said lands measuring 4763.39 acres (approximately) or 1927.65 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto:

Note 1. The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the District Magistrate, Dhenkanal (Orissa), or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited, (Revenue Section) Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note 2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acqisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows :—

"(1) Any person intersted in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the object or an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this act".

Note 3. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act.

SCHEDULE

Natidi Block

(Talchar Coalfield)

All Rights

Serial number	Village	Tahsil	Police Station
1.	Danra	Talchar	Colliery
2.	Kuchianali	-do-	-do-
3.	Jambhubahali	-do-	-do-
4.	Badajorda	-do-	-do-
5.	Mahendrapur	-do-	-do-
6.	Chintamanipur	-do-	-do-
7.	Natidi	-do-	-do-
8.	Baulapur	-do-	-do-

Drg. No. Rev/90/82 Dated 29-12-82

(Showing lands to be acquired)

Number	District	Area	Remarks
24	Dhenkanal	2099.39	Full
13	-do-	100.36	-do-
22	-do-	486.62	-do-
52	-do-	1056.00	Part
121	-do-	271.65	Full
21	-do-	28.93	-do-
83	-do-	334.22	-do-
92	-do-	392.22	-do-

Total area : 4763.39 acres (approximately)
or 1927.65 hectares (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Danra : 1 to 5318.

Plot numbers to be acquired in village Kuchianali : 1 to 272.

Plot numbers to be acquired in village Jambubahali : 1 to 956.

Plot numbers to be acquired in village Badajorda : 1 to 650, 608 (Part), 609 to 675, 676 (Part), 677, 678 (Part), 679 to 681, 682 (Part), 685 (Part), 686 (part), 689 (part), 885 (part), 89 (Part), 890, 891 (part), 892 (part), 895 (part), 896 (part), 897 to 924, 925 (part), 926 (part), 978 (part), 979 (part), 980, 981 (part), 989 (part), 990 (part), 991 to 994, 995 (part), 996 to 1169, 1173, 1174 (part), 1175, 1176 (part), 1177 (part), 1178 to 1380, 1381 (part,) 1382 to 1403, 1404 (part), 1405 to 1420, 1421 (part), I422 (part), 1424 (part), 1426 (part), 1427 (part), 1432 (part), 1436 (part), 1437 (part), 1438 (part), 1439, 1440, 1441 (part), 1442 to 1445, 1446 (part), 1447 (part), 1448 (part), 1488 (part), 2214 (part), 2216 (part), 2217, 2218 (part), 2228 (part), 2229 to 2235, 2236 (part), 2237 to 2246, 2247 (part), 2248 (part), 2249 (part), 2251 (part), 2252, 2253, 2254 (part), 2262 (part), 2263 (part), 2271 (part), 2272 (part), 2430 (part), 2932, 2941, 2942, 2946, 2947, 2959, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 3297, 3298, 3324, 3325, 3326, 3357, 3358, 3359, 3385, 3387, 3421 3422, 3427, 3428, 3430, 3431, 3432, 3434, 3435, 11/3437, 11/3438, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3458, 3459, 3462, 3463, 3468, 3470, 3473, 3496, 3526, 3527, 3530 and 3531.

Plot numbers to be acquired in village Mahendrapur : 1 to 442.

Plot numbers to be acquired in village Chintamanipur : 1 to 58.

Plot numbers to be acquired in village Natidi : 1 to 608.

Plot numbers to be acquired in village Baulapur : 1 to 278.

Boundary Description :

A—B line passes along the part northern boundary of village Danra and meets at point 'B'.

B—C line passes along the south western boundary of villages Danra and Kuchianali, Natidi and Baulapur and meets at point 'C'.

C—D line passes along the southern boundary of villages Baulapur, Mahendrapur and part western boundary of village Badajorda and meets at point 'D'.

D—E line passes through plot numbers 2430, along northern boundary plot numbers 606, through plot numbers 608, 682, 685, 686, 689, 678, 676, 885, 889, 891, 892, 895, 895, 926, 925, 978, 979, 981, 989, 990, 995, 1488, 1174, 1176, 1177, 1446, 1447, 1441, 1446, 1438, 1437, 1436, 1432, 1381, 1427, 1426, 1421, 1422, 1404, 2214, 2216, 2218, 2228, 2272, 2236, 2271, 2263, 2262, 2254, 2251, 2247, 2248 and 2249 in village Badajorda and meets at point 'E'.

E—F line passes along the eastern boundary o villages Badajorda and Jambhubahali and meets at point 'F'.

F—G line passes along the eastern boundary of village Danra and meets at point 'G'.

G—A line passes along art northern boundary o village Danra and meets at starting point 'A

[No. 19/5/83-CL]

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 27 मई, 1983

का०आ० 2324—भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3, उपखंड (11) तारीख 9 अक्तूबर, 1982 में पृष्ठ 3697-3698 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3557 तारीख 22 सितम्बर, 1982 में :—

पृष्ठ 3697 पर—अधिसूचना के पैरा 2 की पंक्ति 2 में "नागपुर-440001 दरभंगा के कार्यालय में" के स्थान पर "नागपूर-440001 के कार्यालय में" पढ़ें।

पृष्ठ 3698 पर—(1) अनुसूची में पंक्ति 2 में :—

(क) "झारखंड कोयला क्षेत्र" के स्थान पर "झागराखांड कोयला क्षेत्र" पढ़ें।

(ख) क्रम सं० 1 के सामने ग्राम स्तम्भ के नीचे "कोजी" के स्थान पर "कोर्जा" और उसके पश्चात् "कोजी" शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है "कोर्जा" शब्द पढ़ें।

(ग) क्रम सं० 5 के सामने क्षेत्र स्तम्भ के नीचे "207.600" के स्थान पर "207.608" पढ़ें।

(घ) क्रम सं० 6 के सामने पटवारी सर्किल सं० स्तम्भ के नीचे "126" के स्थान पर "128" और क्षेत्र स्तम्भ के नीचे "012.153" के स्थान पर "82.153" पढ़ें।

(ङ) सीमावर्णन में :—

(i) रेखा झ—ज में :

"झ—ज" रेखा के स्थान पर "झ—ञ" और "उसी ग्राम में बिन्दु "ज पर मिलती है" के स्थान पर" उसी ग्राम में बिन्दू "ञ" पर मिलती है" पढ़ें।

(ii) रेखा "न—ट—ठ—ड—ढ—ण—त—थ—द—ध—न—प" के स्थाम पर "ञ—ट—ठ—ड—ढ—ण—त—थ—द—ध—न—प—क" पढ़ें।

[सं० 19/17/82-सी०एल०]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th May, 1983

S.O. 2524.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O., dated the 22nd September, 1982, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3 sub-section ii) dated the 9th October, 1982, at page 3698 for "S.O." read "S.O." 3557'.

[No. 19/17/82-CL]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27 May, 1983

S.O. **2525**.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1542, dated the 1st April, 1982, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th April, 1982.

At page 1701,-

in column 1. in line 3.
for 6th May ;
read (9th May';
in column 2, in line 12,
for "Bakaro"
read "Bokaro" ;
in line 24,
for '66.5'
read '66.85';

In line 25,
For "329 (part)"
Read "328 (part)";
in line 55,
For "228 to 233 (part)"
Read "228 to 232, 233 (part)";
in line 56,
For '234 of 259'
Read '234 to 259';
in line 58,
For "316 (part) 317"
Read "316 (part), 317 (part) and 372 (part)".

At page 1702

In line 2 in the 1st column
For '79 (part), 94 (part), 124 (part)'
Read '79 (part), 84 (part), 124 (part)'
In line 7
For "251 (part), 252 to 253, 259 (part)'
Read '251 (part), 252 to 258, 259 (part)'
in line 58
For 'Common Voundary'
Read 'Common Boundary'
In line 59 in the 1st. column
For '342, 233'
Read '372, 233'
In line 62
For 'Common Voundary'
Read 'Common Boundary'
In line 10 in the 2nd column
For 'in village Chhokikuri'
Read 'in village Chhotkikuri'
In line 15
For 'plot numbers 176 and'
Read 'Plot numbers 176'
In line 22
For 'acquired u/s (1')
Read 'acquired u/s 9 (1)'
In line 52
For 'Karo Block Sub-Blo'
Read 'Karo Block sub-block'
In line 53
For 'acquired us 9 (1)'
Read 'acquired u/s 9 (1)'

At page 1703

In line 12 in the 2nd column
For 'Plot numbers 183, 179, 178, 177'
Read 'Plot numbers 188, 179, 178,177'

(No. 19/4/82-CL.)

का०आ० 2526:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि से कोयला प्राप्त होने की संभावना है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

2. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र में रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त धनबाद (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1-काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या निदेशक (निगम योजना और परियोजना), ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेडस, सैन्कटोरिया डाकघर दिशेरगढ़ जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय मे किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) नियम 1957 के नियम 5 की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर निदेशक (निगम योजना और परियोजना) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सैन्कटोरिया को भेजेगा।

अनुसूची

दुधापाणी-ब्लाक

रानीगंज कोयला क्षेत्र

ड्राइंग सं० एल०आर०/1935

तारीख 14-7-82

(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित की गई है)

क्रम सं०	मौजा (ग्राम)	थाना संख्यांक (थाना)	पुलिस थाना	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	दुधापाणी	232	चिरकुंडा	धनबाद	187.80	भाग
2.	गलफालबरी	231	चिरकुंडा	धनबाद	372.60	पूर्ण
3.	बृन्दाबनपुर	64	निरसा	धनबाद	32.40	भाग
4.	गोपीनाथपुर	65	निरसा	धनबाद	322.20	भाग
5.	कपासरा	63	निरसा	धनबाद	12.00	भाग

कुल क्षेत्र : 927.00 एकड़ (लगभग)

या 375.14 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन

क-ख रेखा मौजा (ग्राम) कपासरा से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग रेखा मौजा कपासरा और बृन्दावनपुर से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ	रेखा मौजा गोपीनाथपुर की भागतः उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।
घ-ङ	रेखा मौजा बृन्दावनपुर और कपासरा से होकर जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।
ङ-च	रेखा मौजा कपासरा की दक्षिण-पूर्व सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "च" पर मिलती है।
च-छ	रेखा मौजा गलफालबरी और दुधापाणी की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है।
छ-ज	रेखा मौजा दुधापाणी की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है।
ज-झ	रेखा मौजा दुधापाणी की भागतः दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है।
झ-ञ-ट-ठ	रेखाएं मौजा धुधापाणी से होकर जाती हैं और बिन्दु "ठ" पर मिलती हैं
ठ-ड	रेखा मौजा दुधापाणी की भागतः दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है।
ड-ढ	रेखा मौजा गलफालबरी की भागतः पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ढ" पर मिलती है।
ढ-ण-त	रेखाएं मौजा गलफालबरी और गोपीनाथपुर की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "त" पर मिलती है।
त-क	रेखा मौजा गोपीनाथपुर, बृन्दावनपुर और कपासरा से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० 19/92/82-सी एल]

S. O. **2526**.—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby given notice of its intention to prospect for Coal therein;

The plan of the Area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Dhanbad (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1-Council House Street, Calcutta or in the office of the Director (Corporate Planning & Project), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post- Office Dishergarh, District-Burdwan (West Bengal)

Any person interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Director (Corporate Planning and Projects), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, within a period of ninety days from the date of the publication of this notification in the Gazette of India, as required under rule 5 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Rules, 1957.

SCHEDULE

DUDHAPANI-BLOCK
RANIGANJ COALFIELD
Drawing No. LR/1935
Dated : 14-7-82

(Showing lands notified for prospecting)

Sl. No.	Mouza (Village)	Thana Number	Police Station (Thana)
1.	Dudhapani	232	Chirkund
2.	Galfalbari	231	—do—
3.	Brindabanpur	64	Nirsha
4.	Gopinathpur	65	—do—
5.	Kapasara	63	—do—

District	Area in acres	Remarks
Dhanbad	187.80	Part
—do—	372.60	Full
—do—	32.40	Part
—do—	322.20	—do—
—do—	12.00	—do—

Total Area 927.00 acres
(Approximately)
or 375.14 hectares
(Approximately)

BOUNDARY DESCRIPTION :

A-B Line passes through mouza Kapasara and meets at point 'B'

B-C Line passes through mouza Kapasara and Brindabanpur and meets at point 'c'

C-D Line passes along part northern boundary of mouza Gopinathpur and meets at Point 'D'

D-E Line passes through mouzas Brindabanpur and Kapasara and meets at point 'E'.

E-F Line passes along south east boundary of mouza Kapasara and meets at point 'F'.

F-G Line passes along northern boundary of mouzas Galfalbari and Dudhapanki and meets at point 'G'.

G-H Line passes along eastern boundary of mouza Dudhapani and meets at point 'H'.

H-I Line passes along part southern boundary of mouza Dudhapani and meets at point 'I'.

I-J Lines pass through mouza Dudhapani and meet
K-L at point 'L'.

L-M Line passes along part southern boundary of mouza Dudhapani and meets at point 'M'

M-N Line passes along part eastern boundary of mouza Galfalbari and meets at point 'N'.

N-O Lines pass along southern boundary of mouzas
P Galfalbari and Gopinathpur and meet at point 'P'

P-A Line passes through mouzas Gopinathpur, Brindabanpur and Kapasara and meets at the starting point 'A'.

[No. 19/92/82-CL]

का०आ० 2527.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 12 दिसम्बर, 1981 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3351, तारीख 24 नवम्बर, 1981 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 85.54 हैक्टर (लगभग) या 211.37 एकड़ (लगभग) माप की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और पूर्वोक्त परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के बारे में कोई आपत्ति नहीं की गयी है;

और केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 85.54 हैक्टर (लगभग) या 211.37 एकड़ (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 85.54 हैक्टर (लगभग) या 211.37 एकड़ (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक का निरीक्षण कलक्टर, चंद्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

(हिन्दुस्तान लालपेठ विद्युत खान परियोजना, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

सभी अधिकार रेखांक सं० सी०-1(ई)/111/जे०आर०/241882 राजस्व भूमि तारीख 11-3-1981

(जिसमें अर्जित की गई भूमि दर्शित की गई है)

क्रम सं०	ग्राम	पी०सी० सं०	तहसील और जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	माना	6	चन्द्रपुर	60.23	भाग
2.	नन्दगांव	6	चन्द्रपुर	25.31	भाग

कुल क्षेत्र 85.54 हैक्टर (लगभग)

या 211.37 एकड़ (लगभग)

ग्राम माना में अर्जित किए गए प्लाट संख्यां

43, 44, 49, 50, 51 (भाग) 52(भाग), 57 से 62 73 और नाला का भाग ग्राम नंदगांव में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक

1(भाग), 2/1, 2/2-2/3 (भाग), 2/4 (भाग), 3/3-3/4 (भाग), 3/8 (भाग), 3/9 (भाग), 40/2 (भाग), 40/3 (भाग), 40/4 (भाग) और 10/5 (भाग)

सीमा वर्णन

क-ख रेखा ग्राम नंदगांव के प्लाट संख्यांक 3/8, 3/9, 3/3-3/4-2/4 से होकर जाती है और माना और नंदगांव ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग रेखा ग्राम से होकर प्लाट सं० 57 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और प्लाट सं० 51 से होकर आगे जाती है और प्लाट सं० 51 और 54 की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा, ग्राम माना के प्लाट सं० 51, 52 से होकर जाती है और ग्राम की सड़क के पूर्वी ओर बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ रेखा ग्राम माना से होकर ग्राम की सड़क पूर्वी और पार्श्व के साथ-साथ जाती है और प्लाट सं० 44 और 45 की सीमा पर बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ—च रेखा ग्राम माना से होकर प्लाट सं० 44 और 45 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और तब प्लाट सं० 49, 73, 51 और 62 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ आगे जाती है । नाला को पार करते हुए ग्राम नंदगांव से होकर आगे जाती है और प्लाट सं० 2/2–2/3 की पश्चिमी सीमा पर बिन्दु 'च' पर मिलती है।

च—क रेखा नंदगांव के प्लाट सं० 2/2–2/3, 40/5, 40/4, 40/3, 40/2, 3/9 और 3/8 से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० 19/69/82-सी एल]
समय सिंह, अवर सचिव

S. O. **2527**.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 3351, dated 24th November, 1981 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), and published in the Gazette of India Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 12th December, 1981, the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands measuring 85.54 hectares (approximately) or 211.37 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas no objection was made to the acquisition of the lands in the locality aforesaid;

And whereas the Central Government after consulting the Government of Maharashtra is satisfied that the lands measuring 85.54 hectares (approximately) or 211.37 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 85.54 hectares (approximately) or 211.37 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto are hereby acquired;

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur (Maharashtra).

SCHEDULE

Hindusthan Lalpeth Open Cast Project
Wardha Valley Coalfield

District : Chandrapur (Maharashtra)

Plan No. C-1(E)/III/JR/241-882 dt. 3-8-82

(showing the lands acquired)

All Rights
Revenue Land

S. No.	Village	P.C. No.	Tahsil and District	Area in hectares	Remarks
1.	Mana	6	Chandrapur	60.23	Part
2.	Nandgaon	6	Chandrapur	25.31	Part
			Total	85.54 hectares (approximately)	
			or	211.37 acres (approximately)	

Plot numbers acquired in village Mana :

43, 44, 49, 50, 51(P), 52(P), 57 to 62, 73 and part of a nalla.

Plot numbers acquired in village Nandgaon :

1(P), 2/1, 2/2-2/3(P), 2/4(P), 3/3-3/4(P), 3/8(P), 3/9(P) 40/2(P), 40/3(P), 40/4(P) and 40/5(P).

Boundary description :

A—B Line passes through village Nandgaon in plot Nos. 3/8, 3/9, 3/3-3/4 and 2/4 and meets on the common boundary of villages Mana and Nandgaon at point 'B'.

B—C Line passes through village Mana along the eastern boundary of plot No. 57 then proceeds through plot No. 51 and meets on the common boundary of plot Nos. 51 and 54 at point 'C'.

C—D Line passes through village Mana in plot Nos. 51, 52 and meets on the eastern side of village road at point 'D'.

D—E Line passes through village Mana along the eastern side of the village road and meets on the boundary of plot Nos. 44 and 45 at point 'E'.

E—F Line passes through village Mana along the common boundary of plot Nos. 44 and 45 then proceeds along the western boundary of plot Nos. 49, 73, 51 and 62 crossing over the Nalla, proceeds through village Nandgaon and meets on western

boundary of plot Nos. 2/2-2/3 at point 'F'.

F—A Line passes through village Nandgaon in plot Nos. 2/2-2/3, 40/5, 40/4, 40/3, 40/2, 3/9 and 3/8 and joins the starting point at 'A'.

[No. 19/69/82-CL]
SAMAY SINGH, Under Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th May, 1983

S.O. 2528.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) S.O. No. 3297 dated the 1st September, 1982 published at pages 2358-3363 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 18th September, 1982 in the Schedule,-

I.—Under the heading "VILLAGE-DURGAPUR DISTRICT CHANDRAPUR MAHARASHTRA

1. against Case No. 2—for "viotoriabai" read as, 'Victoriabai" and for "Pihilprao" read "Philiprao".
2. against Case No. 14 (A) —in column No. 6, for "Rs 2 870·00" read "2,287.00."
3. against Case No.18 —for "Jairaj." read "Jairaj"
4. against Case No. 4 for "4" read "24"
5. against Case No.32 —for "Yado "read "Yadao"
6. agaiast Case No.40 —for "G" shown—"no need to show";
7. against Case No.42 —for "Kolassawala" read "Kolsawala";
8. against Case No.46 —for "Nagralee" read "Nagrale";
9. against Case No.50 —For "Bafian" read "Baban"
10. against Case No.55 —for "Pranalal" read "Pranlal";
11. against Case No.60 —for "Shalikaram" read "Shalikram";
12. against Case No.64 —for "Dharmji" read "Dharmaji";
13. against Case No.118 —for "122/2f" read "122/2",
14. against Serial No.99 —for "99" read '89";
15. against Case No.134 —for "Bhandrawati" read "Bhadrawati";
16. against Case No.136 — in column No.6, for "22,186.55" read" "22,186.50".
17. against Case No.140 —for "f" shown "no need to show";
18. against Case No.144 — in column No.4 for "128/1" read "128/1" 201/1 201/2
19. against Case No. 123—in column No. 4 for "271/1" read "271/2"

II. Under the heading "VILLAGE-DEOI GOVINDPUR DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA).

1. against Case No. 7B —for "107/35" read "107/6 (P)".
2. against Case No.19 —for "on Chandrapur' read "of Chandrapur".

[No. 13/3/82-CL]
SAMEY SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 1983

का० आ० 2529.—कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने कोयला खान कल्याण संगठन में श्री आर० एस० शिवानी को कोयला खान कल्याण आयुक्त के पद पर 30 मई, 1983 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त किया है।

[सं० ए-12025/(i)-1/80-एम० II/प्रशा०-1]
श्रीमती कृ० सूद, निदेशक

New Delhi, the 30th May, 1983

S.O. 2529.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), the Central Government has appointed Shri R. S. Shivani as Coal Mines Welfare Commissioner in the Coal Mines Labour Welfare Organisation with effect from the forenoon of 30th May, 1983 and until further orders.

[No. A-12025/(i)-1/80-M.II/Adm.I]
SMT. K. SOOD, Director.

कार्यालय मुख्य लेखा नियंत्रक

पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1983

का०आ० 2530.—केन्द्रीय सिविल सेवाएं अस्थाई सेवा, नियम 1965 के नियम 5 के उपखण्ड (1) के परंतुक के अनुसार मैं इसके द्वारा श्री उपेन्द्र सिंह रावत चपरासी (तदर्थ) की सेवा समाप्त करता हूं और निदेश देता हूं कि यह सूचना की अवधि के लिए वेतन तथा भत्ते का उन्हीं दरों पर जिन

पर सेवा समाप्ति के तुरन्त पूर्व पा रहा था दावे का हकदार होगा ।

[सी० 14013(61)82/प्रशासन-I/5311]
प० च० अग्निहोत्री, वेतन लेखा अधिकारी

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF ACCOUNTS

(Department of Supply)

New Delhi, the 2nd March, 1983

S.O. 2530.—In pursuance of the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965, I hereby terminate forwith the service of Shri Umesh Chander Singh Rawat, Peon (adhoc) and direct that he shall be entitled to claim pay plus allowances for the period of notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service

[C-14013(61)82/Admin-I/5311]
P. C. AGNIHOTRI, Pay and Accounts Officer

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1983

का०आ० 2531—आरोविल (आपात्कालीन उपबन्ध) अधिनियम, 1980 (1980 का 59) के खंड 18 के साथ पढ़े जाने वाली धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और केन्द्रीय सरकार के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के आदेश सं० फा० 8-5/80-नीति नियम-1 दिनांक 14 नवम्बर, 1980 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्याय-मूर्ति एल०पी० निगम को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्ति की अवधि एतद्द्वारा 9-11-1983 तक बढ़ाती है ।

[सं० फा० 43-24/82-आई०एन०सी० (आरोविल)]
डी०एस०मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(Deptt. of Education)

ORDER

New Delhi the 18th May, 1983

S.O. 2531.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 18, of the Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980 (59 of 1980), and in continuation of the order of the Central Government in the Ministry of Education and Culture (Department of Education) No. F 8-5/80-PN.I dated the 14th November, 1980 the Central Government hereby extends the terms of appointment of Justice L. P Nigam, retired judge of the Allahabad High Court, as the Administrator for the purpose of the said Act up to 9-11-1983.

[No. F. 43-24/82-INC(Arov)]
D. S MISRA, Jt. Secy.

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली 25 मई, 1983

(पुरातत्व)

का० आ० 2532—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 19 फरवरी, 1983 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग की अधिसूचना सं० का आ० 1142 तारीख 2 फरवरी, 1983 द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित स्मारकों के निकटस्थ या पार्श्वस्थ क्षेत्रों का खनन संक्रियाओं के प्रयोजनार्थ, जिसके अन्तर्गत, जैसा कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 2 के उपनियम (ङ) के अधीन यथापरिभाषित है, खदान क्रिया, उत्खनन, विस्फोटन तथा ऐसी ही प्रकृति की कोई अन्य संक्रियाएं भी हैं प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करने के अपने आशय की सूचना दी थी और उक्त नियमों के नियम 31 के उपनियम (1) की अपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना की एक प्रति संस्मारक के पास सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी थी,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 3 मार्च, 1983 को उपलब्ध करा दी गई थीं

और केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति से जो कोई आक्षेप प्राप्त हुए हैं उन पर सम्यक् रूप से विचार किया गया है ।

अतः केन्द्रीय सरकार, प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्र को खनन संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध घोषित करती है ।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	स्मारक का नाम	प्रतिषिद्ध घोषित किए राजस्व प्लाट संख्यांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	आगरा	किरावली	फतेहपुर सीकरी	फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह	निम्नलिखित गांवों में संपूर्ण खुला क्षेत्र : सीकरी I हिस्सा, सीकरी II हिस्सा,	कुछ नहीं

1	2	3	4	5	6	7
					सीकरी IV हिस्सा, अराजी इम्लाक, कडाऊ बराऊ, दादूपुरा और गुड़ की मंडी	

[सं० 8/4/82-संस्मा०]
डा० (श्रीमती) देबला मित्र, महानिदेशक
और पदेन संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 25th May, 1983

(Archaeology)

S.O. 2532.—Whereas by the notification of the Government of India in the Department of Culture No. S.O. 1142 dated the 2nd February, 1983 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub section (ii) dated the 19th February, 1983, the Central Government gave notice of its intention to declare the areas near or adjoining the protected monuments specified in the Schedule attached hereto to be a prohibited area for purposes of mining operation which as defined under sub-rule (e) of rule 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 includes quarrying, excavating, blasting and any other operation of like nature and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the area as required under sub-rule (1) of rule 31 of the said rules;

And whereas the said gazette was made available to the public on 3rd March, 1983.

And whereas the objections received from the public have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore in exercise of the power, conferred by rule 32 of the Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Rules, 1959, the Central Government hereby declares the said area to be prohibited area for purposes of mining operation.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monuments	Revenue plot numbers declared prohibited	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Uttar Pradesh	Agra	Kiraoli	Fatehpur Sikri	Fatehpur Sikri group of monuments	Entire open area in mauzas Sikri I Hissa, Sikri II Hissa, Sikri IV Hissa, Arazi Imlak, Kandau Barau, Dadu Pura and Gurh ki-Mandi	Nil

[No. 8/4/82- M]
(D. MITRA)
Director General
& EX-OFFICIO JOINT SECRATARY
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली 31 मई, 1983

का० आ० 2533.—चलचित्र (सेंसर) नियम, 1958 के नियम 7 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुरेश माथुर, आई० ए० एस०, को केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक 10-5-83 (अपराह्न) से अस्थायी व्यवस्था के रूप में, संयुक्त सचिव के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष के उक्त पद के कर्त्तव्यों को देखने के लिए नियुक्त करती है। यह नियुक्ति श्री एम० पी० उपासनी संयुक्त सचिव, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार के अधीन कार्य-भार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है, के स्थान पर की गई है।

[फाइल सं० 802/21/82-एफ०सी०]
आर० डी० जोशी, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 31st May 1983

S.O.2533.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952 read with rule 7 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby appoints Shri Suresh Mathur, IAS, Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting to look after the current duties of the post of the Chairman, Central Board of Film Censors, in addition to his duties as Joint Secretary, as a temporary arrangement from 10-5-83

A.N. till the post of Chairman is filled on a regular basis vice Shri S. P. Upasani, Joint Secretary, relieved to join the Government of Maharashtra.

[F. No. 802/21/82-F(C)]

R. D. JOSHI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 मई, 1983

का० आ० 2534—चलचित्र (सेंसरशिप) नियम, 1958 के नियम 10 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री जोसेफ डोमिनिक, आई० आर० एस० (सी० एंड० सी०ई०) को 7-5-1983 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक उस वेतन पर जो भारत सरकार के उप सचिव का है प्रादेशिक अधिकारी केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती है ।

[802/20/82-एफ०सी०]

New Delhi, the 20th May 1983

S.O. 2534.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952) read with rule 10 of the Cinematograph (Censorship) Rules 1958, the Central Government is pleased to appoint Shri Joseph Dominic, IRS (C&CE), on pay as for Deputy Secretary in the Government of India, to officiate as Regional Officer, Central Board of Film Censors, Madras on deputation basis wit effect from 7-5-1983 F.N. until further orders.

[F. No. 802/20/82-F(C)]

नई दिल्ली, 30 मई, 1983

का० आ० 2535—चलचित्र (सेंसरशिप) नियम, 1958 के नियम 10 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री आर० जे० बैले, आई० आर० एस० (सी० एंड सी० ई०), को 12-5-1983 के अपराह्न से अगले आदेश तक, उस वेतन पर जो भारत सरकार के उप सचिव का है, प्रादेशिक अधिकारी केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती है ।

[फाइल संख्या 802/21/82-एफ० (सी)]

के० एस० वेंकटारामन्, अवर सचिव

New Delhi, the 30th May, 1983

S.O. 2535.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with rule 10 of the Cinematograph (Censorship) Rules 1958, the Central Government is pleased to appoint Shri R. J. Beley, IRS (C&CE), on pay as for Deputy Secretary in the Government of India, to officiate as Regional Officer, Central Board of Film Censros, Bombay on deputation basis with effect from 12-5-1983 A.N. until further orders. (F. No. 802/21/82-F(C).

[F. No. 802/21/82-F(C)]

K. S. VENKATARAMAN, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली 28 मई, 1983

का०आ० 2536—स्थायी आदेश संख्या 627 दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक तार महानिदेशक ने कूत्थाटुकुलम/रामामंगलम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-6-83 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-9/83 पीएचबी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 28th May, 1983

S.O. 2536.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specified 16-6-1983 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Koothattukulam/Ramamagalam Telephone Exchange Kerala Circle.

[No. 5-9/83PHB]

नई दिल्ली 1 जून, 1983

का० आ० 2537.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1980 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-6-83 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[सं० 5-11/83 पी०एच०बी०]

त्रिलोकी नाथ, सहायक महानिदेशक (पी० एच०बी०)

New Delhi, the 1st June, 1983

S.O. 2537.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specified 16-6-1983 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Whitefield Telephone Exchange Karnataka Circle.

[No. 5-13/83 PHB]

TRILOKI NATH, Asstt. Director General (PHB)

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 28th May, 1983

S.O. 2538.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron & Steel Company Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th May, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 81 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron & Steel Company Limited, P. O. Jamadoba, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. N. Sinha, Group Personnel Officer of the Company

For the Workman.—Shri Tarini Singh the concerned workman.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

AWARD

Dhanbad, the 13th May, 1983

The present reference arises out of Order No. L-20012-(319)/82-D. III (A), dated, the 9th December, 1982, passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"Whether the action of the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron & Steel Company Limited, in dismissing Shri Tarini Singh Trammer, with effect from 10-5-1982 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement dated 10-5-1983 has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

Reference No. 81 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Jamadoba Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P. O. Jamadoba, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen (Sri Tarini Singh), Ex. Trammer 6 & 7 Pits Colliery.

That it is submitted that the Ministry of Labour and Rehabilitation, Government of India by Order No. L-20012 (319)/82-D-III (A) dated 9-12-1982, referred the following dispute for adjudication by this Honourable Tribunal

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jamadoba Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., in dismissing Sri Tarini Singh, Trammer, with effect from 10-5-82 is justified ? If not to what relief the workman is entitled ?"

That the parties above named beg to submit that after detailed discussion, the dispute referred to the Honourable Tribunal, for adjudication has been settled amicably on the following terms :—

1. That it has been agreed to employ Sri Tarini Singh on his substantive post of Trammer at 6 & 7 Pits Jamadoba Colliery of M/s Tata Iron & Steel Co. Ltd.

2. That Sri Tarini Singh will not be entitled to receive any back wages or any other monetary benefits during the period, he remained dismissed from Steel Cos Service i.e. with effect from 10-5-1982 to the date he resume his duty.

3. That he will however be granted continuity of service only for the purpose of gratuity. The period of absence due to his dismissal shall be treated as "dies-non".

4. That the above terms of settlement fully resolves the dispute pending before the Honourable Tribunal.

5. That the above terms of settlement are fair.

It is therefore humbly prayed that the terms of settlement may be accepted and an Award be passed in terms thereof.

Sd/-
TARIM SINGH

For the Workmen

For Employer.
M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd.,
P. O. Jamadoba,
Dist. Dhanbad.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer

[No. L-20012(319)/82-D III (A)]

New Delhi the 28th May, 1983

S.O.2539.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Madhuband Colliery of Messrs Bharat Coking and their workmen which was received by the Central Government on the 24th May, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 25 of 1981.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Madhuband Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Mudkhurkee, District Dhanbad.

AND

Their Workmen

PRESENT:

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workman—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

AWARD

Dhanbad, dated the 18th May, 1983

By Order No. L-20012(245)/80-D. III.A, dated, the 16th May, 1981, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes

Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the management of Madhuband Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nudkhurkee, District Dhanbad in denying to pay Category-IV wages as Pump Khalasi to Shri Sukar Mahato with effect from the 1st May, 1977 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The case of concerned workman, Sukar Mahato, is that since the time of the out going proprietor he has been working as Pump Khalasi in Madhuband Colliery which was nationalised with effect from 1-5-1972 and has been operating pump of 150 H.P. since long and the management has placed him in Category-III. His further case that he has been demanding Category-IV wages since long but without any success although other Pump Khalasis of B.C.C.L. who are operating pumps of more than 75 H.P. are getting Category-IV. His claim, therefore, is that he should be given Category-IV wages with retrospective effect from the date of the nationalisation of the colliery on 1-5-1972.

3. The case of the management, on the other hand, is that in the Central Coal Wage Board Recommendations two categories have been fixed for Pump Khalasis, namely, Category-II and Category-III. Pump Khalasis operating pumps upto 35 H.P. have been placed in Category-II and Pump Khalasis operating pumps of 35 H.P. and above have been placed in Categories-III, with a further clause that Pump Khalasis operating two or more pumps would be placed in one category higher than the category to which he is entitled for operating only one pump. It is the further case of the management that some Pump Khalasis who were already in Category-IV at the time of the nationalisation or who were driving more than one pump of 75 H.P. were put in Category-IV by the present management but since the concered workman has been operating only one pump of 150 H.P. he has been rightly placed in Category-III in accordance with the Central Coal Wage Board Recommendations read with National Coal Wage Agreements I & II and he is not entitled to Category-IV wages as claimed by him.

4. Two witnesses have been examined on behalf of the management and on behalf of the concerned workman only he has examined himself. Two documents have also been exhibited on behalf of the management.

5. Sri K. C. Nandkeolyar (MW-2) is Dy. Chief Personnel Manager (Operation, Western Division) of B.C.C.L. at Karmik Bhawan, Dhanbad, who is dealing with industrial relations cases of all the Areas in the Western Division i.e. Area I to VI and XII. The present reference concerns Area I. He has deposed that for the purpose of fixing the categories of different workers and their wages the management has been following the Central Coal Wage Board Recommendations and National Coal Wage Agreements I & II and the Pump Khalasis in the entire B.C.C.L. Organisation have been put in two catergories i.e. Category-II and Category-III as per recommendations of the Central Coal Wage Board, and a Pump Khalasi operating a pump of upto 35 H.P. has been put in Category-II and a Pump Khalasi operating pump of 35 H.P. and above has been put in Category-III. He has further deposed that if any Pump Khalasi operates more than one pump he is placed in one category higher than the one to which he is otherwise entitled, and in this way if a Pump Khalasi of Category-III operates more than one pump of 35 H.P. or above he will be put in Category-IV. His aforesaid evidence is quite in keeping with the Central Coal Wage Board Recommendations, Vol-II, Appendix V, at pages 44 and 45, wherein also a Pump Khalasi operating pump upto 35 H.P. has been put in Category-II and a Pump Khalasi operating Pump of 35 H.P. and above has been put in Category-III, with a foot note that if he operates more than one pump he will go to a higher category. I, therefore, see no reason to disbelieve the aforesaid evidence of Sri K. C. Nandkeolyar (MW-2). In his cross-examination he has denied the suggestion made on behalf of the concerned workman that in Area No. II Pump Khalasis oeprating single pump of 75 H.P. and above are getting Category-IV wages.

5. Sri Om Prakash Joshi (MW-1) is working in Madhuband Colliery since June, 1979 as Senior Personnel Officer. He has got prepared a list showing the number of pumps with H.P. operating in Madhuband colliery of B.C.C.L. together with the names of the Pump Khalasis operating those pumps and their categories. The said list is also signed by Sri A. N. Yadav, the Manager of the colliery, and it has been proved and marked Ext. M-1. According to him, all the Pump Khalasis in Madhuband colliery are either in Category-II or in Category-III as shown in the list and none is in Category-IV, and in this colliery there are three pumps of 150 H.P. and all the Pump Khalasis who operate those 150 H.P. pumps are in Category-III. He has also deposed that to his knowledge no pump Khalasi in any colliery in Area I is getting Category-IV wages and all of them are getting either Category-II or Category-III wages, and he had also occasion to work in Area III in Govindpur colliery and there also Pump Khalasis are being paid Category-II or Category-III wages and none is paid Category-IV wages, and whenever occasion arises for any Pump Khalasi to operate more than one pump he is for that period given wages of one category higher than the category in which he is ordinarily placed. There is also nothing in his cross-examination to disbelieve his aforesaid evidence. In his cross-examination he has categorically denied the suggestion made to him that Pump Khalasis operating pumps of 150 H.P. are being paid Category IV wages in Madhuband colliery or in any colliery in Area I.

6. The concerned workmen, Sukar Mahato (WW-1), has admitted in his cross-examination that he operates pump of 150 H.P. in 18-A Seam which is a closed mine and in that 18-A Seam there is only one pump, and it is a fact that he operates only one pump. He has, however, tried to improve upon his case in the written statement by stating in his examination-in-chief that besides operating one pump of 150 H.P. he also supervises other pumps which go out of order and he puts them in working order. This improvement in his evidence has oviously been made by him to get a category higher than Category-II in which he is placed according to the Central Coal Wage Board Recommendations, Vol-II, Appendix V, at page 45 which has classified a Pump Khalasi operating pump of 35 H.P. and above in Category-III. But I do not accept his aforesaid improvement in his evidence in his examination-in-chief in the absence of any such case in his written statement. Besides, under the foot note of Appendix V a Pump Khalasis who operates more than one pump is entitled to go to a higher category than the category in which he is ordinarily placed and not one who simply supervise other pumps which go out of order and puts them in working order. In order to support his case in his written statement that although he is operating only one pump of 150 H.P. he should be given Category-IV wages on the ground that other pump Khalasis of B.C.C.L. who are operating pumps of more than 75 H.P. are getting Category-IV wages, he has cited the case of one Brahmdeo Singh, Pump Khalasi in Bhrungia Project, who, according to him, is operating a pump of 150 H.P. but is getting Category-IV wages. It, however, appears that Sri B. Joshi, Advocate, appearing for the management, had made enquiry from the Project Officer, Bhurungia Project, about the details of the employment of the said Brahmdeo Singh on which the said Project Officer of Bhurungiya Project in his letter dated 12-3-1983 (Ext. M-2) replied that Brahmdeo Singh is being paid Category IV wages instead of Category-III wages because he is operating more than one pump at one time. Therefore, the work of the concerned workman who is operating only one pump of 150 H.P. is not comparable to the work of the said Brahmdeo Singh who is operating more than one pump at one time.

7. Sri D. Mukherjee, appearing for the concerned workman has cited before me a decision of the Supreme Court in the case of Randhir Singh Vs Union of India and others (1982 Lab. I.C. 806) in which it has been held that though the principle of 'equal pay for equal work' is not expressly declared by our Constitution to be fundamental right, it certainly is a Constitutional goal, and construing Articles 14 and 16 in the light of the Preamble and Art. 39(d) of the Constitution the principle 'Equal pay for Equal work' is deducible from those Articles and may be properly applied to cases of unequal scales of pay based on no classification or irrational classification though those drawing the different scales of pay do identical work under the same employer. The aforesaid principles laid down by the Supreme Court are quite sound so far as they go, but they have got no application to the facts of the present case as in the present case all the Pump Khalasis under the B.C.C.L. who are operating pumps of 35 H.P. and above have been placed in Category-III like the concerned workman and it is only in cases where any pump Khalasi of Category-III has been operating more than one pump likee Brahmdeo Singh of Bhurungia Project that he has been given one higher category-IV as per Central Coal Wage

Board Recommendations Vol-II, Appendix V, pages 44 and 45, which is based on a quite reasonable classification and hence there is no question of any discremination in regard to the concerned workman who is admittedly operating only one pump of 150 H.P. and who has been rightly placed in Category-III.

7. There is, no merit in the case of the concerned workman, Sukar Mahato, and the action of the management in denying to pay Category-IV wages to him as Pump Khalasi with effect from 1-5-1977 is fully justified and he is not entitled to any relief. In the circumstance of the case, however, there will be no order as to cost.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer.
[No. L-20012(245)/80-D.III(A)]

New Delhi, the 23rd May, 1983

S.O. 2540.—In pursuance of section 33(A) ofthe Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the National Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Air India and their workmen, which was received by the Central Government on the 16-5-83.

BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Complaint No. NTB-3 of 1982

(Arising out of Reference No. NTB-1 of 1980)

PARTIES :

Prakash K. Shetty Cleaner, No. 30647 Cabin-Catering Section Air-India, Flat No. 17/3 Air-India Housing Colony, I Bombay-400029. Complainant

Vs.

Air-India, Air-India Building, Bombay-400021. Opp. Party

APPEARANCES :

For the complainant—Mr. M. B. Anpchan, Advocate.

For the opposite party—Mr. B.I. Israni, Advocate.

INDUSTRY : Airlines STATE : Maharashtra

AWARD

Bombay, the 3rd day of May, 1983

This is a complaint filed by the complainant under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947, against the opposite party, Air-India, Bombay.

2. The opposite party by its letter dated 16th June, 1982 communicated to the complaint that as he remained absent without permission his name was struck off from the muster-rolls of the Corporation with effect from 4-4-1982. According to the complainant this action of the opposite party during the pendency of the above mentioned reference NTB-1 of 1980 without having obtained approval under Section 33(2)(b) of the Industrial Disputes Act, 1947, was illegal. The complainant, therefore, prayed that this Tribunal be pleased to direct the opposite party to reinstate the complainant with full back wages and other consequential relief.

3. Mr. Anchan the learned counsel for the complainant, has now filed a pursis in writing that the complainant has been reinstated in service and has reported for duty. He, therefore, prayed that this complaint be disposed of.

4. The comlaint is disposed of as not pressed. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer
[No. L-11014(2)/83-D.II(B)]

New Delhi, the 28th May, 1983

S.O.2541.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Southern Railway Administration and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-5-1983.

BEFORE THIRU T. ARULRAJ, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU, MADRAS

(Constituted by the Government of India)

Tuesday, the 10th May, 1983

Industrial Dispute No. 52 of 1982

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Southern Railway Administration, Cochin and Trichur)

BETWEEN

The workmen represented by

The General Secretary, Southern Railway Construction Workers Union, Ernakulam, Cochin-682016

AND

(1) The Executive Engineer (Construction), Southern Railway, Ernakulam, Cochin-682016.

(2) The Executive Engineer (Construction), Southern Railway, Trichur.

REFERENCE :

Order No. L-41011(6)/82-D.II(B), dated 20-10-1982 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Saturday, the 7th day of May, 1983 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru V. Gopalakrishna Pillai, Advocate for the workmen and of Thiruvalargal M. C. Cherian and T. A. Rajen, Advocates appearing for the Managements and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

This dispute arises out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in Order No. L-41011(6)/82-D.II(B), dated 20-10-1982 of the Ministry of Labour to adjudicate the following issue :

In view of the Railway Board's orders contained in letter No. PG-72/RLT/69-3 dated 12-6-1974 whether the Southern Railway Administration is justified in not paying the scale rate of wages to re-engaged workers who were retrenched earlier and were in receipt of the scale rate of wages at the time of their retrenchment : If not, to what relief are the workmen entitled.

2. According to the allegations in the claim statement, in the year 1974, 179 causal labourers engaged in the construction works of the Southern Railway were retrenched by the Executive Engineer, Construction, Southern Railway, besides 20 other persons. They have worked for a period of six months continuously and they have been drawing scale rate of wages at the time of retrenhment. These retrenched casual labourers were re-employed during different periods both by the Executive Engineer, Construction and Executive Engineer, Trichur. However the above Executive Engineers did not pay the scale rate wages last drawn by them before retrenchment to those retrenched workmen. But on the other hand they were treated as fresh recruits and they were given only market rate of wages, instead of scale rate wages, in spite of Railway Board's letter No. PG. 72/RLT/693, dated 12-6-1974. Even under Section 2-H of the Industrial Disputes Act, the retrenched workers shall be re-employed under the same terms and conditions which existed at the time of retrenchment. This denial of scale rate wages to the members of the Applicant-Union is therefore opposed to the provisions of the Industrial Disputes Act. Hence, it

is prayed an award may be passed directing the Respondents to pay the workmen scale rate of wages.

3. The Respondent in its counter statement contends that the Applicant-Union is not a recognised Union as envisaged in the Railway Establishment Manual and other provisions regarding the recognition of Union by the Railway Board and therefore this dispute at its instance is not maintainable. It is not correct to state that there was any retrenchment of casual labourers in 1973 to 1974. It is true that some casual labourers have been discharged from service on account of their participation in the Railway strike in May, 1974. However, some of them were reinstated on the basis of order of Honourable High Court of Kerala and others on the basis of special general orders passed by the Railway Board. All such casual labourers who were thus reinstated and who were even eligible for scale rate of wages prior to the date of termination have been given scale rate of wages, on their reinstatement. In these circumstances, the contention of Union that these casual labourers have been given only market rate of wages and not scale rate of wages is not correct. Even otherwise, the casual labourers who have completed six months service prior to 1-6-1974 on the strength of the Board's order will not be entitled to claim that benefit of getting scale rate of wages on re-appointment. On re-engagement of such casual labourers, they would be entitled to scale rate of wages only if they again satisfy the condition of six months' continuous service as envisaged in the said Board's Order. This was made clear by subsequent orders of the Board dated 18-1-1977 and 21-10-1980. These orders passed by the Railway Board had the force of statutory rules as per Rule 157 of the Railway Establishment Code Volume-I and a casual labourer working in the Railway is bound by the orders passed by the Railway Board. Section 25-H of the Industrial Disputes Act dots not envisage any such benefit regarding the payment of wages as contended in the claim statement. This industrial dispute is liable to be dismissed in limini as the Union of India is not impleaded as a party. For all or any of these reasons therefore the Petitioners will not be entitled to any relief. It is also contended that out of 189 persons in the list, 15 persons have not been taken back and 17 persons have either left the service after engagement or made permanent. Hence no relief could be given as against these persons

4 The points for determination in this case will be :

(1) Whether this dispute at the instance of Petitioner-Union is maintainable ;

(2) Whether all or any of these 189 persons will be entitled to scale rate of wages and if so from what date ; and

(3) What relief the parties are entitled to.

5. Point No. 1 : Of course, Mr. Gopalakrishna Pillai, learned counsel for the Petitioner contends that if the dispute is to be maintainable, it is not necessary that it should be recognised by the employer and if W.W. 1 and his Union is authorised by the members of the Union to espouse this dispute, it is maintainable. W.W. 1 Thiru L. Robert D'Souza, Secretary of the Petitioner-Union has stated that there are 300 members in the Petitioner-Union and admits though it is a registered one, bearing Registration No. 208/69, this Union is not recognised by the Railways. According to him, all the 189 persons were members of this Union even from 1973. He has not produced any records to show that these persons are members of his Union. However, under original of Ex. W-5, it is resolved by the Union to raise this demand, among other demands. In view of the innumerable decisions, of the Supreme Court, recognition of the Union by the employer is not necessary, and it is enough if the substantial number of the affected persons authorised the Union to espouse the cause of the dispute as in this case. Under these circumstances, this dispute raised by the Union is maintainable.

6. Even though it has been raised in the counter statement that Union of India will be a necessary party, it is not now urged by Mr. Cherian, learned counsel for the Management. As pointed out by Mr. Gopalakrishna Pillai, the reference is whether the Southern Railway Administration is justified in not paying the scale rate of wages implies the Southern Railway represented by two Engineers under whom the 189 persons are said to be working or re-appointed is a party in this case are not Union of India as contended in the counter statement. In these circumstances, Union of India will not be a necessary party and this dispue against the Southern Railway administration represented by two Executive Engineers of Ernakulam and Trichur will be in order. This point I find accordingly in favour of the Petitioner.

7. Point No. 2 : In this case, W.W. 1, Secretary of Petitioner-Union, namely, Southern Railway Construction Workers Union, Ernakulam has stated that about 200 persons were retrenched by the Respondent in 1973, 1974 and 1976 and at the time of retrenchment, they were drawing a sum of Rs. 10.05 ps. in the scale of Rs. 200 to Rs. 250 per mensem. One 13-7-1977 all these retrenched persons were reinstated. After reinstatement, men, workers were paid Rs. 7.35 ps. per day and women workers were paid Rs 5.40 ps. per day for a period of six months, whereas, at the scale rate of wages, they will be entitled to Rs. 11.25 ps. According to him, the persons numbering 189, as mentioned in Ex. W-1, are not in more than 15 years of service and they had continuous service more than 6 months, before retrenchment. He admits however, the service cards will be issued, but he states that they will be issued only when they are sent out of service and on re-appointment, the service cards will be surrendered. He however agrees to confine his claim to those who have been reinstated out of these 189 persons and also in respect of rest of the persons, to such amount, they will be entitled till their confirmation or till they served, after re-appointment. In fact, the Management has filed a memo Ex. M-5 stating that 15 persons Thiruvalargal V. Kesavan, O. J. Benedict, N. K. Balakrishnan, K. P. Paul, K. Narayana Pillai, K. Velu, A. V. Ayyappan, T. K Padamanabhan, C. P. Narayanan Nair, T. K. Balakrishnan, P. Damodharan, P. G. Jose, A. K. Kuttappan, K. A. Pankajakshnan and T. M. Abdulsamad bearing Serial Nos. 1, 3, 12, 13, 18, 35, 37, 40, 43 55 68 121 128 151 and 183 respectivelyinEx. W-1 have not been reinstated and Serial Nos. (27) K. K. Krishnan, (71) K. A. Dasan, (80) K. M. Ramachandra Kurup, (152) K. T. Gopalan and (147) Ambisenkaran left their service, first two on 5-9-1977, 4th on 15-10-1977, 3rd on 25-10-1977 and 5th on 26-10-1977, after their reappointment on 13-7-1977 in the case of first, 2nd and 5th and on 21-7-1977 in the case of 3rd and 4th and Serial numbers 2, 4, 6, 15, 24, 30, 31, 41, 46 46 67 26, 25, viz., Thiruvalargal S. Dandapani, C. P. Shanmugham, T. K. Bhaskara Menon, K. P. Thankappan, P C. Appachan, M. K Krishnan, M. C. Chakkrappan, P. P. Thevan, K. R. Sebastian, U. Ramu, P. N. Rajappan Nair and C. K. Prabhakaran have been appointed on regular basis on 20-9-1977 in the case of Seriel Nos. 4, 24, 41, 67 and others on various dates as mentioned in Ex. M-5. As conceded by W.W. 1, therefore, only rest of such persons who have been reappointed would be entitled to the difference between the scale rate of wages and low rate, paid for six months after reinstatement and others reappointed till they were made permanent or they left the service. The point now therefore will be whether under law even such of these Petitioners who have been reappointed will be entitled to any such difference.

8. Mr. Gopalakrishna Pillai, learned counsel for the Petitioner will rely upon Ex. W-2, dated 12-6-1974, the Railway Board's letter to the General Managers of various Railways, regarding wages of casual labour employed in Railway Projects and also the judgements in O. P. 4062/74 and W.A. No. 211/75 on the file of Kerala High Court under Exs. W-3 and W-4 for his contention that the Petitioners will be entitled to count the period of service for six months before retrenchment for purpose of payment of scale rate of wages immediately after re-appointment without for six more months from the date of re-appointment. Mr Cherian will not dispute this proposition as laid therein. On the other hand, he will rely upon Ex. M-1 dated 18-1-1977, Railway Board's letter to the General Managers of All Indian Railways Exs. M-2 and M-3 also Board orders and the judgement of the Kerala High Court in O. P. 2955/80-B under Ex. M-4 in the interpretation of these orders for his contention that this benefit was not available to them, at the time of reappointment. According to him, in as much as reappointment is after Ex. M-1 which is binding on the workers they are bound by the directives given therein, by which a fresh period of six months of continuous service must be completed bfore ever casual labourers is entitled to scale rate of wages.

9. It is true under Ex. W-2, as interpreted under Exs. W-3 and W-4 by a Single Bench as well as Division Bench of the Kerala High Court, any casual employee will be entitled to scale rate of wages if re-employed with effect from 1-6-1974 if he has been put in service, as such, for a period of six months before or after 1-6-1974 If this rule of the Board is to be applied, the Petitioners will be certainly entitled to the difference as prayed for. But however before over these Petitioners could be re-appointed, Board has passed an order or issued a rule under Ex M-1, which means as was observed by the Kerala High Court under Ex. M-4, a casual labourer, who is entitled to the benefits of the orders Ex. W-2, will lose it, if there is break in service of such casual labourer in the same type of work even after six months continuous service. Though however, subsequently under Ex. M-2, dated 21-10-1980, as clarified under Ex. M-3 dated 2-4-1981 it was directed, on completion of works or for non-availability of further productive work, when casual labour on daily wages or in regular scale of pay of 1/30th of the minimum of scale plus Dearness Allowance is discontinued and employed later when work is available such gaps in the service will not count as breaks for the purpose of reckoning of continuous service of 120 days or 180 days as the case may be, under Ex. M-3. it is observed that the order Ex. M-2 is applicable only from the date of issu namely, 21-10-1980 and the provisions thereof cannot be applied with retrospective effect. Under both the orders Exs. M-2 and M-3, it appears there is no change in the benefits conferred under Ex. W-2. It is only under Ex M-1, which was issued on 18-1-1977, benefits acquired by the Petitioners appear to be affected, but in my view, it is not so. In the last sentence of paragraph (2) of Ex. M-1, it is stated, if there is a break in the continuity of employment of such casual labour in the same type of work, they will cease to be entitled to receive wages at 1/30th of the appropriate scale rate. Nowhere in Ex M-1, the word "break" is defined. It is only in Ex M-2, in paragraphs (2) and (3), break is explained in the negative sense. It is stated as follows : Unauthorised absence upto 3 days and authorised absence upto 20 days will not constitute a break in the employment of casual labour" and again "on completion of works or for non-availability of further productive work when casual labour on daily wages or in regular scale of pay of 1/30th of the minimum of scale plus Dearness Allowance is discontinued and employed later when work is available, such gaps in the service will not count as breaks for the purpose of reckoning of continuous service of 120 days or 180 days as the case may be" It goes to the extent of stating that even the period served before discharge will be reckoned for the period of six months if re-employed. In short, it means, break in service is one brought about by the fault of the employee. In this case, it is not so Under these circumstances as there is no break, as defined in Ex M-2, in the continuous service of the Petitioner, they will be entitled to the benefits under Ex. W-2 and even under subsequent orders Exs M-1 to M-3

10. In fact, in O P. 2955 80-B covered under Ex M-4 the dispute was not whether the casual worker should complete fresh period of six months after reappointment for purpose of getting the benefits, but whether a worker who was getting a scale rate of wages will lose it and has to start again fresh period of six months, if he absents himself authorisedly no doubt, for more than 20 days as prescribed under Ex M-2 and the Karala High Court has held that in that case, worker will lose benefits, he was already getting The facts in this case are entirely different If the Kerala High Court has also held that this loss is available even in the case of re-appointment, it is only obiter dictum, not binding on this Court Even granting that it is ratio decidendi and Ex M-1 means only this mischief, with all humility at my command, I hold that it will not be good law and enforceable, in view of judgement of the same Kerala High Court under Exs. W-3 and W-4 which are in all fours to the facts in this case It cannot be disputed that Board orders are statutory rules binding on all parties concerned But I do not think any such order can supercede or set aside the judgement of High Court, rendered under Exs W-3 and W-4 It can only be set aside by higher Court viz., Supreme Court or modified by legislative enactment, but not by the Board by passing such an inconsistent order from time to time. L. Robert D'Souza vs Executive Engineer and another reported in 1982 (1) LLJ at page 330 is not relevant to this case except to highlight that this injustice and unreasonableness in the matter of distribution of low wages, even after 10 to 20 years of service are being perpetuated, in spite of its observation as follows . "A man serving for 10, 20, 30 years at a stretch without break being treated as daily-rated servant, is thoroughly opposed to the notions of socio-economic justice and it is high time that the Railway administration brings this part of the provision of the Manual, antequatian and antediluvian, in fonformity with the Directive Principles of State Policy as enunciated in Part IV of the Constitution" For all or any of these reasons therefor I hold that such of these Petitioners, as conceded by W.W. 1 and in accordance with particulars, furnished under Ex. M-5 will be entitled to scale rate of wages for the period, they have been drawing low rate. This point I find accordingly in favour of the Petitioners

11 Point No. 3 : In the result, an award is passed directing the Respondents to pay the difference between the low rate and the scale rate of wages to all persons except such of the persons and for such of the period, as mentioned in Ex M-3. No costs.
Dated this 10th day of May, 1983

For workmen

W W 1—Thiru T Robert D'Souza.

For Management : None.

DOCUMENTS MARKED

For workmen

Ex W-1/27-11-76—Southern Railway's notice retrenching the workmen.

Ex W-2/12-6-74—Railway Board's letter to the General Managers of the Railways regarding wages of casual labour employed on Railway Projects.

Ex W-3/2-12-74—Kerala High Court's Judgement in O. P. No. 4062/74.

Ex W-4/8-7-75—Kerala High Court's Judgement in W. A. No 211/75.

Ex W-5/11-1-81—Extract of Proceedings of the general body meeting ofthe Union held on 11-1-81 (English translation attached)

For Management

Ex M-1/18-1-77—Railway Board's letter to the General Managers of All Indian Railways regarding wages of casual labour employed in Railway Projects

Ex M-2/21-10-80— Railway Board's letter to the General Manager regarding engagement of casual labour.

Ex M-3/2-4-81—Railway Board's letter to the General Manager regarding engagement of casual labour

Ex. M-4/24-2-83—Kerala High Court's Judgement in O P. No. 2955/80-B.

Ex M 5/27-4-83—Statement showing the workmen who have not been taken for work and who have been in service after Ex. W-1.

THIRU T. ARULRAJ, Presiding Officer

[No. L-41011(6)/82-D II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

New Delhi, the 21st May, 1983

S.O.2542.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the managtment of Hindustan Commercial Bank Ltd Kanpur U.P. and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th May, 1983.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 9 of 1983

In the matter of Disputes between

Shri Babu Kumar Gupta, Clerk, Sambal Branch (Moradabad), Hindustan Commercial Bank Ltd. Moradabad.

AND

Hindustan Commercial Bank Limited, Kanpur, U.P.

PRESENT :

Shri J. C. Dhawan—for the workman.

Shri Prabhat Shukla—for the Management.

AWARD

The Central Government Ministry of Labour, on 1st October, 1982, vide Order No. L-12012/8/82-D. IV(A), made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Hindustan Commercial Bank Limited, in terminating the services of Shri Babu Kumar Gupta, Clerk, Sambal Branch (Moradabad) from 30-6-1978 (afternoon) is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. Today, a settlement arrived at before the Assistant Labour Commissioner (Central), Kanpur on 30-10-1982, has been filed under which Mr. J. C. Dhawan, General Secretary of Hindustan Commercial Bank Employees Congress, Kanpur and Shri Prabhat Shukla, for the Management voluntarily settled the disputes and Mr. Babu Kumar Gupta was given employment as Clerk at Branch Office Sambal District Moradabad, on probation of 6 months within 15 days of the signing of the settlement and the Union agreed not to claim any past benefits and back wages or terminal benefits in respect of the workman as a result of this employment.

3. The workman has been employed in the Bank from November, 1982 and it is requested that a 'No Dispute' Award be made.

4. In view of the voluntary settlement of the dispute between the Management and the Employees' Union and the workman, Shri B. K. Gupta having been employed on probataion in November, 1982, the dispute does not survive for adjudication in the instant case and accordingly, a 'No Dispute Award' is made.

Dated, April 28, 1983.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-12012/8/82-D. IV(A)]

A. K. SAHAMANDAL, Desk Officer.

New Delhi, the 23rd May, 1983

S.O.2543.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the Industrial Disputes between the employers in relation to the Allahabad Bank, Kanpur, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13-5-83.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 105 of 1981

In the matter of disputes between

Shri Rama Kant Tandon, Clerk, Allahabad Bank, The Mall, Kanpur.

Vs.

The Management of Allahabad Bank, The Mall, Kanpur.

PRESENT :

Shri R. P. Srivastava—for the Management

None—for the workman.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, on 30th July, 1981 vide Order No. L-12012/126/79-D.II. A. made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Allahabad Bank the Mall, Kanpur in not promoting Shri Rama Kant Tandon, Clerk as Special Assistant in terms of this Circular No. 18/23/1087 dated 8-4-78 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled and from which date?"

2. Notice was issued to the Management as well as to the President of Allahabad Bank Karamchari Sangh. The Mall, Kanpur. The statement of Claim received has been signed by and is on behalf of Shri Rama Kant Tandon himself and not on behalf of the Union, Allahabad Bank Karamchari Sangh, who had raised the dispute.

3. The matter concerns the non-promotion of Shri Rama Kant Tandon, Clerk as Special Assistant in terms of Circular No. 18/23/1087 dated 8-4-1978. This claim is not covered by Section 2(A) of the Industrial Disputes Act, 1947. In order to be an "industrial dispute" it must be espoused by the Union, i.e. Allahabad Bank Karamchari Sangh, which has not been done in this case and, therefore this Tribunal cannot proceed with this reference and the reference is not proceeded with on the Statement of Claim filed by Shri Rama Kant Tandon, the workman on his own on account of the claim not falling under Section 2(A) of the Industrial Dispute Act, 1947.

May 10, 1983.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-12012/126/79-D.II.A]

S.O.2544.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 13-5-83.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 55 of 1981

In the matter of disputes between

Shri Ram Saran, through U.P. Bank Employees Union, Kanpur.

AND

Allahabad Bank, Hazrat Ganj, Lucknow

PRESENT :

Shri M. K. Verma—for the Management.

Shri Arun Kumar—for the Workman.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, on 7th April, 1981, vide Order No. L-12012/108/80-D.II.A, referred the following disputes to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Allahabad Bank, Hazratganj, Lucknow in not absorbing Shri

Ram Saran, Subordinate Staff in the Bank service and terminating his services from 2-4-80 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. Today, the parties filed a settlement. The All India Allahabad Bank Employees' Co-ordination Committee and Allahabad Bank, on 13-5-82 had reached an agreement under which the workman, Ram Saran was permanently absorbed in the employment of the Allahabad Bank, w.e.f. 13-11-1982.

3. By virtue of the settlement and permanent absorption of the workman, Ram Saran, in the employment of Allahabad Bank, the workman does not press his claim in the instant case in view of its full and final resolution between the parties voluntarily.

4. Under the circumstances, a 'No Dispute Award' is made.

. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12012/108/80-D.IIA]

New Delhi, the 25th May, 1983

S.O.2545.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes following award of the Central Government Industrial Tripunal New Delhi in the Industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank, Jullundur and their workmen which was received by the Central Government on 24-5-83.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA : PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL: NEW DELHI

I.D. No. 101 of 1978

In the matter of disputes between:

Shri Pran Nath Chopra, Village and Post Office Swaddi, District Ludhiana, Punjab

AND

Allahabad Bank, Jullunder.

APPEARANCES:

Workman in person

Chief Law Officer, Mr. M. R. Savvadhikari for the Management.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, on 17th/20th November, 1978, vide Order No. L-12012/98/77-D. IIA., made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the Management of Allahabad Bank in discharging Shri Pran Nath Chopra, Clerk, Jullunder Branch of the Bank w.e.f. 26-3-73 as measure of punishment is legal and justified? If not, what relief is the workman entitled?"

2. Shri P. N. Chopra joined the Allahabad Bank as a clerk and worked for about 13 years. He was placed under suspension on 5-10-70. His case is that no inquiry was conducted against him and he was not informed about his discharge from service. He made an application to the Presiding Officer, Labour Court, Jalandhar under Section 33-C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 claiming wages for the suspension period and the Management in reply to his application submitted on 18-2-1977 that he had been discharged from service w.e.f. 26-3-1973. The Management took up the position before that Labour Court that the discharge was not punitive and the Labour Court, Jullunder gave him full wages for the period upto 26-3-1973.

3. The workman's case is that the Management may be directed to reinstate him in service with continued service with full back wages, because his discharge from service was not legal and proper. This Statement of Claim was submitted on 18-12-1978 with a copy of the order of the Presiding Officer of Labour Court, Jalandhar dated 28-11-1977 allowing him an amount of Rs. 9379.98 with costs of Rs. 150.

4. The Management of Allahabad Bank contested claim. It was pleaded that the reference was not maintainable and the reference was barred by principles of resjudicata, estoppel, waiver and acquisance and under Order 2 Rule 2 of the Code of Civil Procedurt and also barred by time.

5. The Management claimed that the workman was discharged from service for acts of gross misconduct. He was chargesheeted, but he did not reply to the chargesheeted. A proper departmental inquiry was held after serving due notice on Mr. Chopra. The proceedings of the said inquiry were filed before this Tribunal. The Inquiry Officer held the workman guilty of the charges against him. A show cause notice was given to him in terms of Para 19.12 of the Bi-partite Settlement of 1976 in respect of punishment to be inflicted, but the workman did not reply and he was ultimately discharged from Bank-service by order dated 26-3-1973 with which was enclosed memorandum dated 21-3-1973. The terms of that order and the memorandum are as under :—

"Allahabad Bank
Head Office: 14 India Exchange Place,
Calcutta-1

Ref. No. 698

Mai Hiran Gate
Jullundur City
26th March, 1973

REGISTERED ACKNOWLEDGEMENT DUE

Shri Pran Nath Chopra
C/o Shri T. R. Chopra
369/L, Model Town,

Dear Sir,

Enquiry into the charges against your conduct by Shri R. W. Ilwadhi

We enclose a copy of the Office Memorandum dated 21-3-73 issued by Shri R. L. Lewis, the officer authorised to award punishment in terms of the Bi-partite Settlement dated 19-10-1966 and we hereby advice you stand discharged from the Bank's service with effect from the date of this letter.

We are enclosing a cash order for Rs. 2099|10 comprising your emoluments for three months.

In view of the fact that the applications under section 33 C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 are pending before the Labour Court Jullundur, we are making application to the Honourable Cour for approval of our action as aforesaid.

You may apply for and receive your dues on account of Provident Fund and Gratuity etc. separately in due course.

Yours faithfully,
Sd/-
Manager.

MEMORANDUM

Whereas the Memorandum dated 7-10-1972 issued by me and sent to Shri Pran Nath Chopra (under suspension) a clerk of Jullundur City Branch, by registered Post due for acknowledgement was received back undelivered with the remark 'Refused' and whereas a further letter bearing No. E/9173 dated 15-12-1972 was addressed by me to Shri Chopra and sent to him by Registered A/D post requiring him to show cause against the proposed punishment to discharge him from service and whereas no cause has been shown by Shri Chopra, I hereby direct that the punishment as proposed, i.e., discharge from service shall be given effect to as from the date, the instructions contained herein are received by the Branch concerned. Shri Chopra will not be entitled to any salary or allowances or any other benefit for the period he has

been under suspension except the subsitence allowance in terms of the Sastry Award.

R. L. LEWIS
PUNISHING AUTHORITY
C/O ESTABLISHMENT DEPARTMENT
HEAD OFFICE

Calcutta
Dated: 21st March, 1973.
Shri Pran Nath Chopra,
C/o Shri T. R. Chopra
House No. 369-L,
Model Town,
Jullundur City,
The Manager,
Allahabad Bank,
Jullundur City.

6. The evidence of the parties has been recorded and I have heard the workman as well as the representative of the Management. The preliminary objections of the Management have no substance. There is no limitation prescribed and there is no judgement which may operate resjudicata. There is no estoppel against a statute because the workman claims that his termination of service is illegal and he seeks statutory protection under Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 and there is no estoppel against the rights conferred by a statute. The written arguments filed by th eManagement have been gone into by me fully.

7. The question in this case is a simple one and that is, whether the discharge simpliciter of the workman under Para 19.12 of the Bi-partite settlement without following the procedure and complying with the requirements of Section 25 F of the Industrial Disputes Act, 1947 is valid or not. Admittedly, the Management did not make the order of discharge by way of punishment. It was an order of simple discharge and it is on that basis that the Labour Court, Jullundur allowed full wages to the workman till 25-3-1973.

8. Mr. Savvadhikari urges that the Tribunal cannot substitute its opinion regarding the quantum of punishment and when the discharge simpliciter was ordered for misconduct. The Tribunal could not interfere when the facts were proved in a proper inquiry held and if the workman did not choose to participate in the inquiry, it was his own fault.

9. He argued that the action of the Management could not be termed "Retrenchment" and was not within the purview of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. Here the discharge or dismissal was for committing certain misconduct and the same did not amount to "retrenchment".

10. Mr. Savvadhikari also pointed that Mr. Chopra was an untruthful person who avoided replying to the chargesheet and avoided participation in the inquiry and further avoided replying to the show cause notice issued by the Management but is was the Management that was consideratie and lenient and in view of the past record did not dismiss from service but only discharged from service simply by condoning his misconduct. The workman was said to be so untruthful that even denied the receipt of Rs. 6104.38, his entric Provident Fund Amount by voucher M-5 and the Management had to incur expenses and examined the Handwriting Expert, Mr. R. S. Bal to prove his signatures and the payment made to him. The nature and character of Mr. Chopra were said to be such as not entitled aim to any relief before this Tribunal.

11. The first Bi-partite Settlement, para 19.12(C) is relevant and is in the following terms:—

"19.12(c)—In awarding punishment by way of disciplinary action the authority concerned shall take into account the gravity of the misconduct, the previous record, if any, of the employee and any other aggravating or extenuating circumstances that may exist. Where sufficiently extenuating circumstances exist the misconduct may be condoned and in case, such misconduct is of the 'gross' type, he may be merely discharged with or without notice or on payment of a month's pay and allowances, in lieu of notice. Such discharge may also be given were the evidence is found to be insufficient to sustain the charge and where the bank does not, for some reason or other, think it expedient to retain the employee in question any longer in service. Discharge in such cases shall not be deemed to amount to disciplinary action."

12. The Management has taken action by way of discharge under that para. But it is now settled law that the Bi-partite Settlement is overridden by the provisions of the Industrial Disputes, 1947. The Sastry Award of 1953 specifically stated in para 561 that the diretions given in various matters that fall under "Standing Orders" taking the term in its wider significance should be understood as being subject to the provisions of any law for the time being in force and for that reason, the section would apply, if there be an industrial dispute and dispute is referred to a Tribunal for adjudication.

13. The Supreme Court in the case of "Santosh Gupta Vs. State Bank of India: 1980 (I LLJ 72, ruled that the definition of "Retrenchment" in Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act, 1947 was remarkably vide and it included termination of service for any reason whatsoever. The only exceptions were termination of service as a punishment inflicted by way of disciplinary action, voluntary retirement of the workman, retirement of a workman on reaching the age of superannuation and termination of the services of the workman on the ground of continued ill-health. That was also a case of bank employee and the provisions of the Industrial Disputes Act 1947 including Section 25-F of the said Act were held to be applicable.

14. Similar is the case here. Mr. P. N. Chopra is a bank employee whose services have been terminated under para-19.12(c) of the Bipartite Settlement on condoning his misconduct which was proved in the inquiry and he was merely discharged on payment of month's pay and allowances in lieu of notice. But in view of the afosesaid ruling of the Supreme Court that Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 being applicable to this workman, it was necessary to give this workman retrenchment compensation before his services could be terminated. That was not done.

15. The Supreme Court is further clear that in cases where Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 is applicable and the termination of services is affected without complying with the provisions of Section 25-F(a) and (b) of the I.D. Act, the order of termination is void abnitio and reinstatement in service must ordinarilly follow with full back wages and continuous service.

16. Unfortunately for the Bank-Management, They did not have Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 in mind when they terminated the services of Shri Pran Nath Chopra not by way of purishment, but by way of discharge simpliciter w.e.f. 26-3-1973 and the action of the Management must be held to be void and cannot be maintained and cannot be held to be legal and justified.

17. Howver, thisis a case where the Management held an inquiry and the workman was found guilty in the inquiry on several counts of misconduct and the Management took bona fide action against the workman under the impression that the First Bi-partite Settlement, Para 19.12 was applicable without having recourse to provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. About 10 years had elapsed since the termination of services of the workman and his efficiency as a bank employee now is very much in doubt after being 10 years in wilderness.

18. Under the circumstances, it appears to be a fit case where in place of re-instatement of service, compensation may be allowed to him. A consolidated amount of Rs. 50,000 in liue of back wages and reinstatement in service appears to be proper in the circumstances of the case as compensation to him. This is besides the amount of Provident Fund that he had already received from the Management. There will be no order as to costs in the circumstances of the case.

19. The award is made in terms aforesaid.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
N. K. VERMA, Desk Officer
[No. L-12012/98/77-D. II. A]

नई दिल्ली, 29 मई, 1983

का० आ० 2546.—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम के उप नियम (1) और नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र के तारीख 20 दिसम्बर, 1980 के भाग 2, खंड, 3 उप खंड (ii) के पृष्ठ 4376 पर प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3587 में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार श्रम राज्य मंत्री को केन्द्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त करती है और उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

क्रमांक (1) के लिए और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

"(1) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय —अध्यक्ष"
मे राज्य मंत्री, नई दिल्ली ।

[संख्या-यू-123018/2/80-एम० 5/डब्ल्यू-2]

New, Delhi, the 29th May, 1983

S.O.2546.—In exrcise of the powers conferred by Section 6 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976) read with sub-rule (1) of rule 3 and sub-rule (2) of rule 4 of Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978 and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3587 published at page 4376 of Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 20th December, 1980, the the Central Government hereby appoints the Minister of State for Labour to be the Chairman of the Central Advisory Committee and makes the following amendments in the said notification namely :—

For serial No. (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Minister of State in the Ministry of Labour and Rehabilitation, New Delhi ..Chairman".

[F. No. U-23018/2/80-M.V/W. II]

नई दिल्ली, 28 मई, 1983

का० आ० 2547.—केन्द्रीय सरकार लौह अयस्क खान तथा मैंगजीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम 1978 के नियम-3 के साथ पठित लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस० वी० सालगावकर, मैसर्स वी० एम० सालगांवकर एण्ड ब्रो० प्रा० लि०, सालगांवकर हाउस, वासो-दा-गामा, गोआ को लौह एवं मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार परिषद का सहयोजित सदस्य नियुक्त करती है ।

[फा० सं० यू-23017 (10)/80-एम० 4/डब्ल्यू-2]
कंवर राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 28th May, 1983

S.O. 2547.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) read with rule 3 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1979, the Central Government hereby appoint Shri S. V. Salgaocar, M/s. V. M. Salgaocar & Bros. (P) Ltd. Salgaocar House Vaco-da-gama, Goa, as copted member in the Central Advisory Committee for Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund.

[F. No. U-23017(10)/80-M. IV/W.II]
KANWAR RAJINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मई, 1983

का० आ० 2548.—औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड, जादवपुर, कलकत्ता को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के सभी उपबन्धों से छूट देती है, बशर्ते कि प्रबन्धतंत्र श्रमिकों की वर्तमान सेवा शर्तों में उनकी सहमति के बिना इस तरीके से संशोधन नहीं करेगा, जो कि श्रमिकों के प्रतिकूल हो ।

[संख्या एस-12014/2/82-डी० 1 (ए)]
एस० एच० एस० अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 21st May, 1983

S.O..2548.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946) the Central Government hereby exempts the Industrial establishment, National Instruments Ltd., Jadavpur, Calcutta, from all the provisions of the said Act for the period of three years with effect from the date of the issue of this notification, subject to the condition that the management will not modify the existing service conditions of the workmen in a manner prejudicial to them without their concurrence.

[No. S-12014/2/82-DIA]
S. H. S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 1983

का० आ० 2549.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 29 मई, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले

ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् --

"चिंगलपुट जिले में पुन्नेरी तालुक में आलमति तथा पेडियानल्लूर राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत समाविष्ट क्षेत्र।"

[संख्या एस-38013/11/83-एच० आई०]
ए० के० भट्टराई, अवर सचिव

New Delhi, the 24th May, 1983

S.O.2549.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 29th May, 1983 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu Namely:—

"Areas comprised within the revenue villages Alamathi and Padianallur in Ponneri Taluk in Chingleput District."

[No. S-38013/11/83-HI]
A. K. BHATTARAI, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983